वर्ष 13 • अंक 11 • 14 पृष्ठ • मूल्य 5 रुपये

शुक्रवार 28 फरवरी 2020

कोलकाता, चंडीगढ़, **नई दिल्ली**, पटना, भोपाल, मुंबई, रायपुर और लखनऊ से प्रकाशित।

भारत का पहला संपूर्ण हिंदी आर्थिक अखबार

बिज़नेस स्टैंडर्ड

www.bshindi.com

पृष्ठ 6

निर्यात प्रतिबंध हटने से 30 प्रतिशत उछला प्याज

अजय त्यागी पृष्ठ 3

संतुलित नजरिये संग त्यागी ने तीन साल संभाला सेबी को

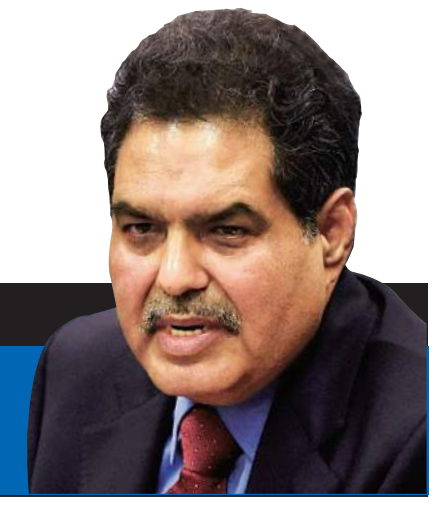

डॉलर रु. 71.60 ▼ 10 पैसे | यूरो रु. 78.30 ▲ 30 पैसे | सोना (10ग्राम) रु 42442 ▼ 42 रुपये | सेंसेक्स 39745.70 ▼ 143.30 | निफ्टी 11633.30 ▼ 45.20 | निफ्टी फ्यूचर्स 11629.30 ▼ 04.00 | ब्रेंट क्रूड 51.10 डॉलर ▼ 01.60 डॉलर

एक नज़र

एजीआर पर आयोग की बैठक शुक्रवार को

संकट से जूझ रहीं दूरसंचार कंपनियों को राहत देने के उपायों पर चर्चा के लिए डिजिटल संचार आयोग (डीसीसी) की अहम बैठक शुक्रवार को होगी। एक सूत्र ने यह जानकारी दी। बैठक में जिन विकल्पों पर विचार किया जा सकता है, उसमें समायोजित सकल आय (एजीआर) बकाया का भुगतान किस्तों में करने की अनुमति देना शामिल है। हालांकि, सूत्रों ने कहा कि वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनियों को राहत उनके अतिरिक्त भुगतान पर निर्भर करेगा।

वोडाफोन आइडिया ने की डेटा महंगा करने की मांग

दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया ने मोबाइल डेटा के लिए शुल्क बढ़ाकर न्यूनतम 35 रुपये प्रति जीबी की दर तय करने की मांग की है जो मौजूदा दर का करीब 7-8 गुना है। कंपनी ने इसके साथ ही एक निर्धारित मासिक शुल्क के साथ कॉल सेवाओं के लिए 6 पैसे प्रति मिनट की दर तय करने की भी मांग की है। अभी मोबाइल डेटा की दरें 4-5 रुपये प्रति जीबी है। कंपनी ने कहा है कि उसकी वित्तीय स्थिति को पटरी पर लाने के लिए 1 अप्रैल से नई दरें लागू की जानी चाहिए।

फ्लिपकार्ट के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही रोकी

राष्ट्रीय कंपनी कानून अपील पंचाट (एनसीएलएटी) ने ई-कॉमर्स क्षेत्र की प्रमुख कंपनी फ्लिपकार्ट के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही गुरुवार को रोक दी। एनसीएलएटी ने इस बारे में राष्ट्रीय कंपनी कानून पंचाट (एनसीएलटी) के आदेश को खारिज करते हुए फ्लिपकार्ट को कॉरपोरेट दिवालिया समाधान प्रक्रिया से निकालने का आदेश दिया। साथ ही एनसीएलटी द्वारा नियुक्त अंतरिम समाधान पेशेवर को कंपनी के रिकॉर्ड और संपत्तियां तत्काल प्रवर्तकों को लौटाने का निर्देश दिया।

ईरान की विमानन कंपनियों की उड़ानें निलंबित

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने ईरान में कोरोनावायरस के प्रकोप को देखते हुए वहां की विमानन कंपनियों का भारत से परिचालन निलंबित कर दिया है। वहां की दो कंपनियां ईरान एयर और महान एयर क्रमश: मुंबई और दिल्ली से उड़ानें संचालित करती हैं। भारत की कोई विमानन कंपनी ईरान के लिए उड़ान संचालित नहीं करती है। पिछले साल करीब दो लाख यात्रियों ने भारत और ईरान के बीच उड़ान भरी।

लक्ष्मी विलास पर बढ़ी बात

टेमासेक ने लक्ष्मी विलास बैंक में 51 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने के लिए तेज की कवायद, जून-जुलाई तक सौदा संभव

हंसिनी कार्तिक
मुंबई, 27 फरवरी

सिंगापुर सरकार की निवेश कंपनी टेमासेक होल्डिंग्स ने नकदी संकट से जूझ रहे लक्ष्मी विलास बैंक (एलवीबी) में नियंत्रण हिस्सेदारी खरीदने के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज कर दी है। इस पूरे मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने कहा कि टेमासेक ने एलवीबी में 51 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने के लिए कंपनी मामलों और वित्त मंत्रालयों से संपर्क साधा है। एक सूत्र ने कहा,'टेमासेक की पहले से वित्तीय क्षेत्र की कई इकाइयों में हिस्सदारी है। लिहाजा, वह इस बात की अनुमति चाहती है कि एक या अधिक भारतीय बैंकों में हिस्सेदारी खरीद सकती है या नहीं।'

सूचीबद्ध कंपनियों की बात करें तो टेमासेक की एचडीएफसी बैंक में हिस्सेदारी है। कंपनी ने पिछले साल ऐक्सिस बैंक और येस बैंक से अपनी हिस्सेदारी बेच दी थी। सरकार से अनुमति मिलने के साथ टेमासेक एलवीबी में 51 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने के लिए समझौते की पेशकश करेगी। एक उच्च पदस्थ सूत्र ने कहा, 'सितंबर 2019 में भारतीय रिजर्व बैंक ने एलवीबी को सुधारात्मक कार्रवाई के तहत रखा था। नियामक के साथ बातचीत के बाद के परिपत्र के अनुसार किसी कमजोर बैंक के पुनर्गठन या बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए विदेशी बैंक कुछ शर्तों के साथ इस सीमा से अधिक हिस्सेदारी भी खरीद सकते हैं। डीबीएस बैंक इंडिया नियामकीय शर्तों के तहत एलवीबी में हिस्सेदारी खरीद कर भारत में अपनी उपस्थिति मजबूत करना चाहती है।

सूचीबद्ध कंपनियों में टेमासेक का निवेश

कंपनी	करोड़ रुपये में
टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज	52
एचडीएफसी बैंक	27
रिलायंस इंडस्ट्रीज	25
लार्सन ऐंड टुब्रो	19

12 महीनों में अहम निकासी

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स	ऐक्सिस बैंक
मदरसन सूमी	बायोकॉन
भारत फोर्ज	येस बैंक

स्रोतः ब्लूमबर्ग संकलनः बीएस रिसर्च

बैंक ने कहा है कि उसकी पूंजी निवेश संरचना कैथलिक सीरियन बैंक की तरह ही होगी।' 31 दिसंबर तक एलवीबी का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 3.46 प्रतिशत था, जो अनिवार्य 9 प्रतिशत स्तर से कहीं कम है। इससे बैंक को भारत में सबसे कमजोर बैंक के तौर पर वर्गीकृत किया जा सकता है। 31 दिसंबर 2019 तक बैंक का कुल ऋण आवंटन 17,535 करोड़ रुपये और जमा राशि (डिपॉजिट) 23,565 करोड़ रुपये थी।

समझा जा रहा है कि टेमासेक शुरू में एलवीबी में हिस्सेदारी खरीदने के लिए अपनी भारतीय बैंकिंग इकाई डीबीएस बैंक इंडिया (डीबीएस सिंगापुर की सहायक इकाई) का सहारा ले सकती है। मई 2016 में आरबीआई ने विदेशी बैंकों को किसी भारतीय बैंक में 10 प्रतिशत तक हिस्सेदारी खरीदने की अनुमति दी थी। आरबीआई

बिजनेस स्टैंडर्ड इंश्योरेंस राउंड टेबल

फोटो: कमलेश पेडणेकर

(बाएं से) एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के प्रेजिडेंट अभिजित गुलानीकर, इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस की एमडी एवं सीईओ आरएम विशाखा, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के एमडी राज कुमार, बिज़नेस स्टैंडर्ड के कंसल्टिंग एडिटर तमाल बंद्योपाध्याय, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ के एमडी एवं सीईओ एनएस कन्नन, एचडीएफसी लाइफ के ईडी सुरेश बदामी और पॉलिसीबाजार के सह-संस्थापक और ग्रुप सीईओ यशीष दहिया।

जीवन बीमा कंपनियां बेचेंगी स्वास्थ्य पॉलिसी!

जीवन बीमा कंपनियों को स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी बेचने की मंजूरी देने पर विचार के लिए एक समिति गठित होने से एक बड़ी बहस शुरू हो गई है। बीमा नियामक आईआरडीए ने इस समिति का गठन किया है। बीमा उद्योग से जुड़े लोगों का मानना है कि नियामक के इस कदम से उन स्वास्थ्य बीमा कंपनियों सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचेगा, जिनकी उपस्थिति केवल इसी कारोबार में है। गैर-जीवन बीमा कंपनियों पर असर थोड़ा थोड़ा कम होगा, क्योंकि वे दूसरे खंडों में भी कारोबार करती हैं।

'बिज़नेस स्टैंडर्ड इंश्योरेंस राउंडटेबल 2020' में बीमा क्षेत्र से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। ज्यादातर जानकारों का मानना है कि बीमा नियामक के इस कदम से भारत में स्वास्थ्य बीमा का प्रसार बढ़ेगा क्योंकि जीवन बीमा कंपनियों का वितरण नेटवर्क अच्छा है। पृष्ठ 3

आरआईएल-ब्रुकफील्ड इनविट देगा आकर्षक ब्याज

देव चटर्जी
मुंबई, 27 फरवरी

आरआईएल-ब्रुकफील्ड इनविट (इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स) अपने धनाढ्य निवेशकों से अधिक रकम जुटाने और निवेशकों को आकर्षक ब्याज भुगतान पर विचार कर रही है। कंपनी के इस कदम का फरवरी में पेश बजट में पेश प्रस्तावों से सीधा नाता है। बजट के अनुसार नए वित्त वर्ष में लाभांश वितरण कर (डीडीटी) का भुगतान प्राप्तकर्ता को करना होगा। बजट प्रस्तावों के बाद इनविट और रीट इक्विटी निवेशकों के लिए आकर्षक नहीं रह गए हैं। इस वजह से इन ट्रस्ट्स को रकम जुटाने में परेशानी आ रही है।

दूसरे शब्दों में कहें तो आरआईएल-ब्रुकफील्ड इनविट निवेशकों को लुभाने के लिए उन्हें अधिक ब्याज की पेशकश करेगी। निवेशक उन देशों से निवेश कर बचाने में सक्षम होंगे, जहां ऋण योजनाओं पर अपेक्षाकृम कम विदहोल्डिंग टैक्स लगता है। इस बारे में एक सूत्र ने कहा कि ऋण योजनाओं से निवेश करने से कर बचाने में मदद मिल सकती है।

आरआईएल-ब्रुकफील्ड इनविट से जुड़े मामले की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने कहा, 'बजट के बाद ट्रस्ट सभी विकल्पों पर विचार कर रहा है। इनमें अधिक ब्याज के साथ ऋण की पेशकश भी शामिल है।' फंड 25,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना पर काम कर रही है। इसने इस संबंध में बाजार नियामक सेबी को मसौदा विवरणिका सौंपी है। अंतिम विवरणिका में बजट में हुए बदलाव का भी जिक्र किया जाएगा। इनविट का कारोबार ढांचा म्युचुअल फंडों की तरह ही होता है। वे निवेशकों से रकम जुटाकर ढांचागत परियोजनाओं में निवेश करते हैं।

टेक विनिर्माण पर नई नीति जल्द!

अरूप रायचौधरी और नेहा अलावधी
नई दिल्ली, 27 फरवरी

देश में स्मार्टफोन, सेमी कंडक्टर और अन्य महंगे प्रौद्योगिकी उत्पादों के विनिर्माण को बढ़ाने देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल जल्दी ही एक नई योजना पर विचार कर सकता है। बिज़नेस स्टैंडर्ड को मिली जानकारी के मुताबिक यह योजना मॉडिफाइड स्पेशल इनसेंटिव पैकेज स्कीम (एमएसआईपीएस), इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स (ईएमसी) और इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट फंड (ईडीएफ) जैसी योजनाओं का स्थान ले सकती है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2020-21 के आम बजट में इस योजना की घोषणा की थी। इस योजना को आकार देने की रफ्तार बढ़ा दी गई है क्योंकि चीन में कोरोनावायरस के प्रकोप के कारण कंपनियां वहां से अपनी विनिर्माण इकाइयों को अन्यत्र ले जाने पर विचार कर रही हैं।

वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'चीन की स्थिति को देखते हुए इस योजना के प्रारूप, उसके तौर तरीकों को तय करने और इसे शुरू करने की प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही है। जो कंपनियां चीन से अपनी विनिर्माण इकाइयों को बाहर ले जाना चाहती हैं, हमने उनके साथ बात की है और इसमें हमें अवसर नजर आ रहा है।'

सूत्रों के मुताबिक इस योजना में कई प्रस्ताव हैं जिन्हें मंत्रिमंडल की मंजूरी की जरूरत होगी।

सबसे ज्यादा आवक कहां से

देश	राशि (अरब डॉलर)
चीन	15.3
हॉन्ग कॉन्ग	6.8
सिंगापुर	2.1
दक्षिण कोरिया	2.1
जर्मनी	1.1

स्रोतः वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

इनमें अधिकांश प्रस्ताव इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के हैं। मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, 'इन प्रस्तावों को मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और कुछ हफ्तों में इन्हें हरी झंडी मिल सकती है। कुछ प्रस्तावों पर वित्त मंत्रालय के साथ चर्चा की जा रही है।'

अधिकारियों के मुताबिक योजना की कुछ बारीकियों पर काम किया जा रहा है। ऐसी संभावना है कि नई योजना का कुल खर्च मौजूदा योजनाओं के लिए आवंटित बजट से थोड़ा अधिक होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी के बजट में 2020-21 के लिए इन तीन योजनाओं को 980 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जबतिक 2019-20 के संशोधित अनुमानों में यह राशि 690 करोड़ रुपये और बजट अनुमानों में 986 करोड़ रुपये थी।

सीतारमण ने 1 फरवरी को पेश बजट में देश में मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और सेमी कंडक्टर पैकेजिंग के विनिर्माण पर केंद्रित एक योजना की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि इसके बारे में विस्तृत जानकारी बाद में दी जाएगी। विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने पिछले सप्ताह सीतारमण के साथ बैठकों में इस बात पर जोर दिया था कि भारत को दीर्घकालीन विनिर्माण क्षमता बनानी चाहिए और चीन पर निर्भरता खत्म करनी चाहिए। वित्त मंत्री ने इसी महीने मीडिया के साथ बजट बाद संवाद में कहा था कि चीन का विकल्प तलाश रही करीब 10-12 कंपनियों ने सरकार से बात की है। उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि हमसे उनकी उम्मीदें वाजिब हैं।' सूत्रों का कहना है कि विभिन्न सरकारी विभागों में इस बारे में बात चल रही है जिनमें वित्त मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, नीति आयोग और इलेट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय शामिल हैं।

एमएसआईपीएस योजना 2012 से 2018 तक चलाई गई थी और इसके तहत 10 साल तक कई तरह के प्रोत्साहन दिए गए थे। इनमें विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) में 20 फीसदी और गैर-एसईजेड में 25 फीसदी पूंजी सब्सिडी शामिल थी।

खबरों में रहे स्टॉक

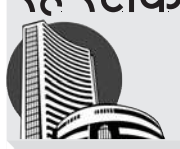

राइट्स

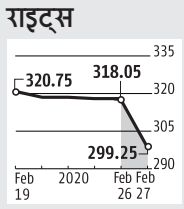

सरकार ओएफएक्स के जरिये 10 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगी

₹ 318.05 पिछला बंद भाव
₹ 299.25 आज का बंद भाव
▼ 5.91 %

सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज

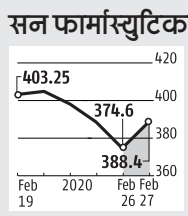

कंपनी ने अमेरिकी बाजार में मधुमेह की देवा पेश की

₹ 374.60 पिछला बंद भाव
₹ 388.40 आज का बंद भाव
▲ 3.68 %

मिश्र धातु निगम

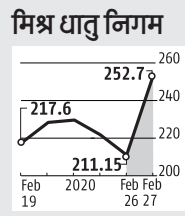

बीएसई-500 सूचकांक में सबसे ज्यादा चढ़ने वाले शेयरों में शामिल

₹ 211.15 पिछला बंद भाव
₹ 252.70 आज का बंद भाव
▲ 19.68 %

इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन

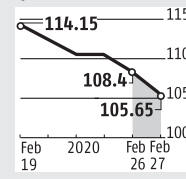

बाजार पूंजीकरण 1 लाख करोड़ रुपये से नीचे फिसला

₹ 108.40 पिछला बंद भाव
₹ 105.65 आज का बंद भाव
▼ 2.54 %

विप्रो

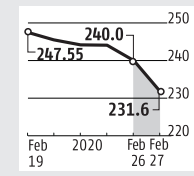

विश्लेषकों को राजस्व वृद्धि की संभावना नहीं दिखने से शेयर में बड़ी गिरावट

₹ 240.00 पिछला बंद भाव
₹ 231.60 आज का बंद भाव
▼ 3.50 %

संक्षेप में

एचपीसीएल ने पेट्रोनेट में हिस्सेदारी खरीदी

सरकारी कंपनी ओएनजीसी और इसकी सहायक इकाई हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) ने पेट्रोनेट एमएचबी लिमिटेड में बैंकों के समूह की हिस्सेदारियां करीब 371 करोड़ रुपये में खरीद ली है। आठ सरकारी बैंकों के एक समूह की पेट्रोनेट में 34.56 प्रतिशत हिस्सेदारी है। इस कंपनी में ओएनजीसी की 32.72 प्रतिशत हिस्सेदारी है। कंपनी में एचपीसीएल की भी इतनी ही हिस्सेदारी है। पेट्रोनेट के पास मंगलूरु में पेट्रोलियम उत्पादों की एक पाइपलाइन का मालिकाना हक है। दोनों कंपनियों ने इसके लिए बैंकों के समूह को अलग-अलग 185.38 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। *भाषा*

जेट के कर्जदाता नए सिरे से मंगाएंगे रुचि पत्र

बंद पड़ी एयरलाइन जेट एयरवेज की कर्जदाताओं की समिति ने विमानन कंपनी के लिए नए सिरे से रूचि पत्र आमंत्रित करने का निर्णय किया है। कंपनी फिलहाल ऋण शोधन प्रक्रिया से गुजर रही है। जेट एयरवेज ने बुधवार को बीएसई से कहा, 'जेट एयरेवज के कर्जदाताओं की समिति (सीओसी) की आठवीं बैठक 18 फरवरी को हुई और ई-मतदान 25 फरवरी को हुआ। बैठक में सीओसी ने नए सिरे से रूचि पत्र आमंत्रित करने का निर्णय किया है।' *भाषा*

बीएस बातचीत

भारत में राजस्व भागीदारी बढ़ाने पर रहेगा जोर

पिछली तिमाही आय में सुधार के संकेत दिखने के बाद आईटी सेवा कंपनी कॉग्निजेंट 2020 को वृद्धि की संभावनाओं वाले वर्ष के तौर पर देख रही है। चेन्नई में हाल में कंपनी की बोर्ड बैठक में शामिल हुए कॉग्निजेंट के मुख्य कार्याधिकारी **ब्रायन हम्फ्रीज** ने **टी ई नरसिम्हन** और **गिरीश बाबू** के साथ बातचीत में आईटी कंपनी की आगामी विकास योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। पेश हैं बातचीत के मुख्य अंश:

चौथी तिमाही के प्रदर्शन में कॉग्निजेंट के लिए 2020 में सुधार का संकेत मिला। क्या कंपनी राजस्व वृद्धि के संदर्भ में अपने प्रतिस्पर्धियों के साथ मुकाबला कर सकेगी?

हमने लगातार तीन तिमाहियों से वाल स्ट्रीट के अनुमान को मात दी है। दरअसल, 5 फरवरी को हमारी ताजा आय घोषणा के बाद, शेयर अगले दिन 10 प्रतिशत चढ़ गया था। मेरा मानना है कि वाल स्ट्रीट में हमारे मालिक कॉग्निजेंट में नया जोश देख रहे हैं। वह हमें एक स्पष्ट रणनीति के बारे में हमें काम करते देख रहे हैं। मेरा मानना है कि इस साल वृद्धि की रफ्तार तेजी होनी चाहिए और 2021 में भी तेजी रहेगी। इसलिए हम उम्मीद के साथ वर्ष 2020 में प्रवेश कर रहे हैं। यह वर्ष क्रियान्वयन का वर्ष होगा।

भारत प्रमुख डिलिवरी केंद्र के तौर पर कॉग्निजेंट के लिए महत्वपूर्ण बना रहेगा?

भारत कॉग्निजेंट के लिए आगे भी अहम भूमिका निभाएगा। भारत कॉग्निजेंट के लिए आत्मा है। यहां हमारे लगभग 200,000 कर्मचारी हैं, जो कुल कर्मचारी आधार का दो-तिहाई हैं। देश में कर्मियों की संख्या में वृद्धि आने वाले वर्षों में भी बरकरार रहेगी। इस साल हम भारत में 23,000 फ्रेशर्स की नियुक्ति कर रहे हैं। कॉग्निजेंट ब्रांड यहां बेहद मजबूत बना हुआ है। हम भारत में निवेश बनाए रखेंगे और यही वजह है कि मैं यहां हरेक 6-8 सप्ताह में आता हूं।

क्या आप नए क्षेत्रों में अपने पोर्टफोलियो में बदलाव लाएंगे?

हमने अपने पोर्टफोलियो में बदलाव किया है। मौजूदा समय में कॉग्निजेंट का 24 प्रतिशत राजस्व उत्तर अमेरिका से बाहर से आता है। हमारी रणनीतिक महत्वाकांक्षा यहां हमारी राजस्व भागीदारी बढ़ाने की है। कंपनी द्वारा किए गए पांच में से तीन अधिग्रहण यूरोपीय कंपनियों से संबंधित थे। मैं अंतरराष्ट्रीय बाजारों में 20 प्रतिशत की चक्रवृद्धि दर से वृद्धि देखना चाहता हूं। हमारी रणनीति के हिस्से हैं- हम अपने पारंपरिक व्यवसाय को सुरक्षित बनाए रखना चाहते हैं और इसमें हम अपनी डिलिवरी को अनुकूल बनाना चाहते हैं। हमें अंतरराष्ट्रीय तौर पर तेजी लानी होगी और प्रौद्योगिकी परामर्श व्यवसाय बढ़ाना होगा। रणनीति का दूसरा हिस्सा चार मुख्य आधारों - क्लाउड, डेटा एनालिटिक्स, डिजिटल इंजीनियरिंग और आईओटी पर केंद्रित है।

क्या आप कॉग्निजेंट की नियुक्ति योजना के बारे में बता सकते हैं?

हमने इस साल लगभग 25,000 लोगों को नियुक्त करने या उन्हें डिजिटल कौशल के साथ फिर से प्रशिक्षित करने की योजना बनाई है। इनमें से कुछ फ्रेशर होंगे, जबकि कुछ को पुन: प्रशिक्षित किया जाएगा। इस साल 23,000 नए स्नातक हमारे साथ जुड़ेंगे, जो पिछले साल की नियुक्तियों के मुकाबले 30 प्रतिशत ज्यादा है। आप हमारी नियुक्तियों में तेजी देखेंगे और यह भविष्य का एक बेहद मजबूत संकेत है।

एक राजनेता ने हाल में कॉग्निजेंट के खिलाफ मद्रास उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी जिसमें भारत में इकाइयों के विकास के संबंध में रिश्वत देने का आरोप लगाया गया था। इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है?

मैं भारत में किसी व्यक्तिगत मुकदमेबाजी या खबर पर प्रतिक्रिया देना नहीं चाहता। बेहद महत्वपूर्ण सवाल यह है कि मैं इसे लेकर आश्वस्त हूं कि हमारे पास विश्वस्तरीय मानकों और अनुपालन वाली टीम है।

संतुलित नजरिये संग त्यागी ने तीन साल संभाला सेबी को

श्रीमी चौधरी
नई दिल्ली, 27 फरवरी

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के प्रमुख अजय त्यागी का तीन वर्ष का कार्यकाल उनके संतुलित नजरिये के लिए याद रखा जाएगा। हिमाचल प्रदेश कैडर के 1984 बैच के आईएएस अधिकारी त्यागी ने बाजार नियामक के मुखिया के तौर पर बहुत बड़ा बदलाव लाने से परहेज ही किया लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज, नैशनल स्टॉक एक्सचेंज और पीडब्ल्यूसी जैसे बड़े कॉर्पोरेट घरानों के खिलाफ कार्रवाई करने से भी नहीं हिचके।

त्यागी के कार्यकाल में सेबी ने कंपनी शासन, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई), भेदिया कारोबार, म्युचुअल फंड और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से जुड़े कई अहम नियमों में बड़े बदलाव किए। इनमें से अधिकांश नियमों के क्रियान्वयन में किसी तरह का व्यवधान भी नहीं देखने को मिला।

हाल ही में त्यागी ने सेबी में अपने कार्यकाल के आकलन के बारे में पूछे जाने पर कहा था कि यह काफी अच्छा अनुभव रहा। उन्होंने इस बात का खास तौर पर जिक्र किया कि सार्वजनिक विमर्श में यकीन रखने के साथ ही उन्होंने पारदर्शी तरीके से अपना काम करने की कोशिश की।

त्यागी को जानने वाले कहते हैं कि सेबी प्रमुख के तौर पर उन्होंने सही मंशा से काम किया लेकिन प्रमुख हितधारकों के विचारों को जगह देने के लिए उन्हें अक्सर समायोजन भी बिठाना पड़ा। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं: कंपनियों को 24 घंटे के भीतर अपने बैंक ऋण चूक का खुलासा करने के लिए कहने वाले परिपत्र को अंतिम पलों में वापस ले लेना या कंपनियों के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक पदों को अलग करने के लिए तय मियाद को आगे बढ़ा देना। त्यागी को बाजार नियामक के तौर पर सेबी की स्वायत्तता बनाए रखने के लिए सरकार के साथ तनातनी में भी उलझना पड़ा था। आम तौर पर शांत एवं संयत रहने वाले त्यागी गत जुलाई में नॉर्थ ब्लॉक के गलियारे में उत्तेजित नजर आए थे। इसकी वजह यह थी कि कुछ दिनों पहले पेश किए 2019-20 के बजट में सेबी अधिनियम 1992 के संशोधन का प्रावधान रखा गया था ताकि सेबी के तीन-चौथाई सरप्लस फंड को सरकार को हस्तांतरित किया जा सके। त्यागी ने इस कदम का विरोध करते हुए कहा था कि ऐसा करना निवेशकों एवं बाजार दोनों के लिहाज से प्रतिकूल है। इसके पहले भी सरकार के साथ त्यागी का मतभेद इस कदर बढ़ गया था कि आर्थिक मामलों के विभाग के तत्कालीन सचिव सुभाष गर्ग को सेबी बोर्ड से अलग हो गए और उनकी जगह पर एक निचले रैंक के अधिकारी को नियुक्त किया गया। उसके बाद से सेबी की अधिकांश समितियों में वित्त मंत्रालय का एक प्रतिनिधि मौजूद है। कुछ लोगों की नजर में यह सेबी के दर्जे को कमजोर करने की कोशिश है।

अपोलो टायर्स घटा रही खर्च

टी ई नरसिम्हन
चेन्नई, 27 फरवरी

कंपनी ने वाहन क्षेत्र में मंदी को देखते हुए वित्त वर्ष 2020 और वित्त वर्ष 2021 में खर्च घटाने पर जोर दिया है

अपोलो टायर्स ने वर्ष 2019-20 में अपने पूंजीगत खर्च में लगभग 300 करोड़ रुपये तक की कमी लाने का निर्णय लिया है। वाहन क्षेत्र में मंदी को देखते हुए कंपनी ने वित्त वर्ष 2021 में भी पूंजीगत खर्च में इसी तरह की कटौती की योजना बनाई है। प्रस्तावित पूंजीगत खर्च मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में कंपनी के नए संयंत्र और उसकी हंगरी स्थित इकाई में होगा। बुधवार को अपोलो टायर्स ने घोषणा की कि निजी इक्विटी फर्म वारबर्ग पिनकस अपनी सहयोगी एमेराल्ड सेज के जरिये कंपनी में लगभग 1,080 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। कंपनी ने कहा है कि इस रकम का इस्तेमाल कॉरपोरेट उद्देश्य के लिए किया जाएगा, हालांकि सूत्रों का कहना है कि कुछ हिस्सा प्रस्तावित पूंजीगत खर्च के लिए इस्तेमाल होगा।

शेयरखान बाई बीएनपी पारिबा में वाहन विश्लेषक भारत ज्ञानानी ने कहा कि कोष उगाही से कंपनी की बैलेंस शीट मजबूत होगी और उसके कर्ज-पूंजी अनुपात में सुधार आएगा। साथ ही वारबर्ग पिनकस के इक्विटी निवेश से व्यवसाय में वृद्धि की संभावना का भरोसा बढ़ा है। वारबर्ग को प्रबंधन बोर्ड में भी जगह मिलेगी जिससे अपोलो टायर्स में बोर्ड एवं प्रशासनिक मजबूत बढ़ेगी। कुल मिलाकर यह कंपनी के लिए सकारात्मक घटनाक्रम है। विश्लेषकों के साथ ताजा बातचीत के दौरान कंपनी के प्रबंधन ने कहा, 'कंपनी ने वर्ष की शुरुआत लगभग 2,700 करोड़ रुपये के पूंजीगत खर्च अनुमान के साथ की जिसे घटाकर 2,400 करोड़ रुपये किया गया है। पिछले 9 महीनों के दौरान कंपनी ने लगभग 2,000 करोड़ रुपये का पूंजीगत खर्च किया है।'

भारत को मिलीं यूएसएफडीए की कम चेतावनी

सोहिनी दास
मुंबई, 27 फरवरी

अमेरिकी दवा विनियामक द्वारा भारतीय फार्मा के लिए विनियामकीय जांच कड़ी करना उद्योग के लिए चिंता की बात है। हालांकि दीर्घकालिक आंकड़े बताते हैं कि भारतीय इकाइयों को चीन और अमेरिका की तुलना में अमेरिकी विनियामक से कम संख्या में चेतावनी-पत्र प्राप्त हुए हैं।

वित्त वर्ष 15 से 19 के बीच भारत में स्थित इकाइयों को अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (यूएसएफडीए) से 66 चेतावनी-पत्र मिले हैं, जबकि चीन में स्थित इकाइयों को 73 चेतावनी-पत्र और अमेरिका की इकाइयों को 97 चेतावनी-पत्र मिले हैं। यूएसएफडीए के अनुपालन कार्यालय के विनिर्माण गुणवत्ता निदेशक फ्रांसिस गॉडविन द्वारा यहां आयोजित एक कार्यक्रम में साझा किए गए आंकड़े बताते हैं कि भारत ने अपने पड़ोसी देश चीन से बेहतर प्रदर्शन किया है, जबकि अमेरिका को फॉर्म्युलेशन और थोक दवा आपूर्ति में उसकी बड़ी हिस्सेदारी रहती है।

जीवन बीमा कंपनियां स्वास्थ्य पॉलिसी बेचें तो फायदा

गैर-जीवन बीमा कंपनियों को जीवन बीमा कंपनियों से कड़ी टक्कर मिलेगी, लेकिन उनमें ज्यादा विशेषज्ञता आएगी

सुब्रत पांडा
मुंबई, 27 फरवरी

(बाएं से) मार्श इंडिया के कंट्री हेड एवं सीईओ संजय केडिया, रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ अनुज गुलाटी, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के एमडी एवं सीईओ भार्गव दासगुप्ता और फ्यूचर जेनेराली के एमडी और सीईओ अनूप राव *फोटो : कमलेश पेडणेकर*

जीवन बीमा कंपनियों को मुआवजा आधारित स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी बेचने की मंजूरी देने की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए समिति गठित करने के बीमा नियामक के कदम से बीमा उद्योग में एक बड़ी बहस शुरू हो गई है। इस क्षेत्र से जुड़े ज्यादातर लोगों का मानना है कि अगर नियामक अपने इस कदम पर आगे बढ़ता है तो इससे उन स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचेगा, जिनकी केवल इसी क्षेत्र में मौजूदगी है।

गैर-जीवन बीमा कंपनियां बुरी तरह प्रभावित नहीं होंगी क्योंकि उनके पास ऐसे कई खंड हैं, जिन पर वे ध्यान दे सकती हैं। इसके अलावा वे स्वास्थ्य खंड में भी ज्यादा मुनाफे वाली पॉलिसी बेचने में संभावनाएं तलाश सकती हैं, जिसका अभी तक उनके कुल स्वास्थ्य कारोबार में मामूली हिस्सा है।

एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के प्रमुख (अंडरराइटिंग और रीइंश्योरेंस) सुब्रमण्यम ब्रह्मजोयसुला ने कहा, 'इससे केवल स्वास्थ्य खंड में मौजूदगी रखने वाली कंपनियों को कई खंडों में मौजूदगी रखने वाली बीमा कंपनियों की तुलना में ज्यादा नुकसान होगा। कई खंडों में मौजूदगी रखने वाली कंपनियां बाजार में कई तरह की योजनाएं बेच सकती हैं।'

उन्होंने कहा, 'हालांकि जीवन बीमा कंपनियों का बेहतर वितरण नेटवर्क है। लेकिन यह चीज भी ध्यान में रखी जानी चाहिए कि स्वास्थ्य बीमा मुआवजा पॉलिसी थोड़ी जटिल हो सकती हैं और ग्राहकों को उचित सलाह देने के लिए पॉलिसी का गहरा ज्ञान होना जरूरी है। यह ऐसा क्षेत्र है, जिनमें शुरुआती दौर में गैर जीवन बीमा कंपनियां बढ़त में रह सकती हैं।'

ज्यादातर जानकारों का मानना है कि बीमा नियामक के इस कदम से भारत में स्वास्थ्य बीमा का प्रसार बढ़ेगा क्योंकि जीवन बीमा कंपनियों का वितरण नेटवर्क अच्छा है। इस वजह से वे स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र का दायरा सुधारने में गैर-जीवन बीमा कंपनियों की तुलना में बेहतर स्थिति में होंगी। वर्ष 2015 से पहले जीवन बीमा कंपनियों को मुआवजा आधारित पॉलिसी और लाभ आधारित पॉलिसी बेचने की मंजूरी थी। लेकिन 2015 में नियामक ने फैसला किया कि जीवन बीमा कंपनियां को मुआवजा आधारित पॉलिसी बेचने की मंजूरी नहीं होगी, वे केवल लाभ आधारित पॉलिसी ही बेच पाएंगी।

उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा कि स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र में हमेशा गैर-जीवन बीमा कंपनियों का दबदबा रहा है। लेकिन अंडरराइटिंग और दावों के प्रबंधन में क्षमता बनाना महंगा है। इसके चलते एकल स्वास्थ्य बीमा कंपनियां और सामान्य बीमा कंपनियां अपने पोर्टफोलियो को बड़ा और लाभकारी बनाने में कड़ी जद्दोजहद कर रही हैं।

जीवन बीमा कंपनियों के मुताबिक मानव बीमारी और मानव की मौत में संबंध है। वहीं मोटर से नुकसान और मानव बीमारी एवं मृत्यु में कोई संबंध नहीं है। इस वजह से जीवन बीमा कंपनियों का मुआवजा आधारित स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी बेचना ज्यादा तर्कसंगत है।

बिज़नेस स्टैंडर्ड इंश्योरेंस राउंडटेबल 2020 में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ एनएस कन्नन ने कहा, 'जीवन बीमा उद्योग का नेटवर्क व्यापक है। अगर आप एलआईसी को देखें तो उनके पास 12 लाख एजेंट हैं। वहीं अन्य सभी कंपनियों के करीब 10 लाख एजेंट हैं। इसलिए 22 लाख एजेंट स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी बेचेंगे, जिनका प्रसार जीवन बीमा से भी बहुत कम है। यह न केवल एलआईसी बल्कि उद्योग एवं देश के लिए बहुत बदलावकारी साबित होगा।'

अश्विन पारेख एडवाइजरी सर्विसेज के प्रबंध निदेशक अश्विन पारेख के मुताबिक, 'शुरुआत में चार दशक पहले स्वास्थ्य बीमा को एक क्षेत्र के रूप में सामान्य बीमा के तहत रखा गया था, जबकि दुनियाभर में इसे जीवन बीमा का ही विस्तार और और जीवन बीमा के ज्यादा नजदीक माना जाता है। उसके बाद सरकारी क्षेत्र की चार सामान्य बीमा कंपनियों ने मेडिक्लेम पॉलिसी शुरू कीं, जो केवल बड़ी बीमारियों के मुआवजे की जरूरत ही पूरी करती हैं।' हालांकि उन्होंने कहा कि ये पॉलिसी प्राथमिक और द्वितीयक चिकित्सा के लिए कोई कवर नहीं मुहैया कराती हैं। एक सामान्य बीमा कंपनी के सीईओ ने कहा कि अगर सामान्य बीमा कंपनियों के कुछ खंडों को खोला जाता है तो जीवन बीमा के कुछ खंडों को भी खोला जाएगा। जीवन बीमा खंड अपने आप में बढ़ता क्षेत्र है। अगर ज्यादा कंपनियां जागरूकता फैलाएंगी तो वे इसका ज्यादा फायदा उठा सकती हैं। इसलिए विशेषज्ञों ने कहा कि इसे विकासात्मक लक्ष्य के रूप में देखा जाना चाहिए। देश में स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र का दायरा बहुत सीमित है, इसलिए बीमा कंपनियां इस प्रतिस्पर्धा का स्वागत कर रही हैं और इस क्षेत्र में जीवन और गैर-जीवन बीमा कंपनियों के पास बढ़ने के बहुत मौके हैं। एचडीएफसी लाइफ के कार्यकारी निदेशक सुरेश बादामी ने बिज़नेस स्टैंडर्ड राउंडटेबल 2020 में कहा कि अगर स्वास्थ्य खर्च पर 100 रुपये खर्च होते हैं तो इसमें से 62 रुपये व्यक्ति की जेब से निकलते हैं।

पॉलिसी बाजार डॉट कॉम के मुख्य कारोबार अधिकारी (जीवन बीमा) संतोष अग्रवाल ने कहा, 'प्रारुपित नियमनों के जरिये जीवन बीमा कंपनियां एक्चुरियल मॉडलों को लागू कर सकती हैं और समय-समय कीमतों की समीक्षा कर सकती हैं। इस कदम से ग्राहकों को तगड़ा फायदा होगा क्योंकि इससे उनके और उनके परिवार के लिए सुरक्षित रहने के विकल्प बढ़ जाएंगे।'

- **आईआरडीएआई ने जीवन बीमा कंपनियों को मुआवजा आधारित स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी बेचने की मंजूरी देने की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए समिति गठित की**
- **जीवन बीमा कंपनियों का वितरण नेटवर्क बड़ा है, इसलिए वे स्वास्थ्य बीमा का बढ़ा सकती हैं दायरा**
- **जीवन बीमा कंपनियों का कहना है कि इस कदम को मंजूरी दी गई तो ग्राहकों को तगड़ा फायदा होगा**
- **एकल स्वास्थ्य बीमा कंपनियां सबसे ज्यादा प्रभावित होंगी, गैर-जीवन बीमा कंपनियों के लिए बढ़ेगी प्रतिस्पर्धा**

कोरोनावायरस से बाजार लगातार हलाकान

सुंदर सेतुरामन
मुंबई, 27 फरवरी

बेंचमार्क सूचकांक बुधवार को लगातार पांचवें दिन गिरे क्योंकि दुनिया भर में कोरोनावायरस फैलने और दिल्ली में अशांति से निवेशक चिंतित हैं। विश्लेषकों ने कहा कि निवेशक इस वजह से चिंतित हैं कि कोरानावायरस महामारी में तब्दील हो सकता है और वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि को रोक कर सकता है।

इस सप्ताह विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने घरेलू इक्विटी बाजारों से 10,000 करोड़ रुपये की निकासी की है, जिससे सूचकांक करीब चार फीसदी लुढ़का है। उनकी निकासी गुरुवार को और अधिक थी क्योंकि उनकी बिकवाली 3,127 करोड़ रुपये की लिवाली से अधिक थी।

बाजार से जुड़े लोगों ने कहा कि कोरोनावायरस के फैलने के अलावा राष्ट्रीय राजधानी में अशांति से निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई है। दिल्ली के घटनाक्रम से देश की उदार लोकतंत्र और निवेश की एक अच्छी जगह की छवि पर धब्बा लगा है। सेंसेक्स गुरुवार को 143 अंक या 0.36 फीसदी लुढ़ककर 39,746 पर बंद हुआ। निफ्टी 50 सूचकांक 45 अंक या 0.39 फीसदी गिरकर 11,633 पर बंद हुआ। इन दो सूचकांकों के अलावा बीएसई के भी सेक्टोरल सूचकांक सत्र में गिरकर बंद हुए।

अवेंडस कैपिटल के सीईओ एंड्रयू हॉलैंड ने कहा, 'बाजारों में कोरोनावायरस को लेकर चिंता बढ़ी है।' उन्होंने कहा कि निवेशक यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि इसका दुनियाभर में कंपनियों पर क्या असर पड़ेगा। बाजार से जुड़े लोगों ने कहा कि अगर बाजार को घरेलू निवेशकों की खरीदारी का समर्थन नहीं मिला तो ये और गिर सकते हैं। उन्होंने पिछले दो कारोबारी सत्रों में हर दिन 3,000 करोड़ रुपये से अधिक के शेयर खरीदे हैं।

तनाव के समय मुस्तैदी दिखाएं म्युचुअल फंड

जश कृपलानी
मुंबई, 27 फरवरी

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के पूर्णकालिक सदस्य जी महालिंगम ने 27 लाख करोड़ रुपये के आकार वाले म्युचुअल फंड उद्योग के जोखिम-प्रबंधन तरीकों में सुधार की जरूरत बताते हुए कहा है कि तनावपूर्ण स्थितियों में औचक बिक्री रोकने के लिए उद्योग एक प्रारूप बनाए।

सेबी के वरिष्ठ सदस्य ने गुरुवार को कहा कि तरलता एवं संक्षिप्त योजनाओं संबंधी मानकों में पिछले साल की गई सख्ती को उत्प्रेरक के तौर पर देखा जाना चाहिए ताकि म्युचुअल फंड उद्योग के जोखिम-प्रबंधन तरीकों को बेहतर किया जा सके। महालिंगम ने भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के 14वें म्युचुअल फंड सम्मेलन में कहा कि फंडों को अधिक रचनात्मक भूमिका निभाने की जरूरत है, जब सवाल निवेश वाली कंपनियों में अपनाई जा रही कंपनी शासन परिपाटी की निगरानी का हो। उन्होंने कंपनी के प्रस्तावों पर मतदान से म्युचुअल फंडों के परहेज करने पर सवाल उठाया।

कॉफी डे को ग्लोबल टेक पार्क बिक्री की रकम मिली

देवाशिष महापात्र
बेंगलूरु, 27 फरवरी

कॉफी डे एंटरप्राइजेज (सीडीईएल) को ग्लोबल विलेज टेक पार्क बिक्री के समझौते के तहत प्राइवेट इक्विटी कंपनी ब्लैकस्टोन और रियल्टी फर्म सालारपुरिया सत्वा ग्रुप से पहला भुगतान हासिल होने की खबर है।

बेंगलूरु की कॉफी चेन को लगभग 150 करोड़ रुपये की पूंजी हासिल हुई है। इस सौदे में टेक पार्क का मूल्यांकन 2,700 करोड़ रुपये पर किया गया। पिछले साल अगस्त में ग्लोबल विलेज टेक पार्क में हिस्सेदारी घटाने के अपने निर्णय के बावजूद यह सौदा लेनदारों की सहमति नहीं मिल पाने की वजह से अधर में लटका हुआ था। खासकर येस बैंक से अनापत्ति प्रमाण पत्र लंबित था, जिससे सौदे की गणना में विलंब हुआ। एक सूत्र ने कहा, 'बकायेदारों से सभी मंजूरियां मिलने के बाद ग्लोबल विलेज टेक पार्क सौदा पूरा हो गया है। शेष रकम अगले कुछ सप्ताह में चुका दी जाएगी।'

यह पूंजी मिलने से कॉफी चेन के लिए कार्यशील पूंजी स्थिति में सुधार आने की संभावना है। इस रकम का एक बड़ा हिस्सा कंपनी का कर्ज घटाए जाने में इस्तेमाल होने की संभावना है। इससे आने वाली तिमाहियों में कंपनी को बकाया ब्याज घटाने में भी मदद मिलेगी। जुलाई 2019 तक समूह पर कुल कर्ज 4,970 करोड़ रुपये था, जिसमें टैंगलिन डेवलपमेंट्स की देनदारियां 1,622 करोड़ रुपये थीं। सीडीईएल की प्रमुख कॉफी रिटेलिंग इकाई कॉफी डे ग्लोबल का कुल कर्ज 1,097 करोड़ रुपये था। सूत्रों का कहना है कि ग्लोबल विलेज टेक सौदे से प्राप्त होने वाली रकम में से लगभग 2,000 करोड़ रुपये का इस्तेमाल कर्ज घटाने में किया जाएगा। सीडीईएल ने अपना ब्रोकरेज व्यवसाय 'वे2वेल्थ सिक्योरिटीज' जनवरी में श्रीराम ऑनरशिप ट्रस्ट को बेच दिया था।

पिछले साल सीडीईएल के संस्थापक चेयरमैन वी जी सिद्धार्थ के निधन के बाद यह समूह ऊंची ब्याज लागत की वजह से नकदी संकट का सामना कर रहा है।

नए नियमों से महंगा होगा ऑडिट

रुचिका चित्रवंशी
नई दिल्ली, 27 फरवरी

ताजा नियमों के तहत चालू वित्त वर्ष से ही ऑडिट रिपोर्ट में ज्यादा खुलासे करना अनिवार्य किया गया है, जिससे ऑडिटर अपने काम के लिए फीस बढ़ा सकते हैं। चार बड़ी नेटवर्क कंपनियों में से एक के वरिष्ठ कार्याधिकारी ने कहा, 'नए दिशानिर्देशों के लागू होने से फीस बढ़ेगी, लेकिन इस वर्ष के लिए फीस की बातचीत पहले ही हो चुकी है।'

सरकार ने कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 2020 की अधिसूचना बुधवार को जारी की थी, जिसमें वित्तीय अनुशासन में सुधार की खातिर ऑडिटरों के लिए जरूरी खुलासों की संख्या बढ़ाकर दोगुनी से अधिक कर दी गई है।

अगर काम में बदलाव होता है तो ऑडिट कंपिनयां तय फीस से ज्यादा वसूल सकती हैं। उसके बाद फीस बढ़ोतरी के आग्रह पर कंपनी की ऑडिट समिति विचार करती है, जिसमें उसका निदेशक मंडल शामिल होता है। ये नियम 1 अप्रैल 2019 से शुरू वित्त वर्ष की ऑडिट रिपोर्टों पर लागू होंगे। चार बड़ी ऑडिट कंपनियों में से एक के कार्याधिकारी ने कहा, 'हम थोड़ी बढ़ोतरी के लिए कह सकते हैं लेकिन फीस पहले ही तय हो चुकी है, इसलिए हम कम से कम इस वित्त वर्ष में बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं कर रहे हैं।'

फीस में बढ़ोतरी की मांग हर मामले पर निर्भर करेगी। कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स में पार्टनर अंकित सिंघी ने कहा, 'बड़ी कंपनियों पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा क्योंकि उनमें काम अधिक होता है।' ऑडिट कंपनियां नए नियमों की वजह से काम के बोझ में बढ़ोतरी और अपनी फीस में बढ़ोतरी के स्तर का आकलन कर रही हैं।

नए नियमों में ऑडिटरों के लिए ऑडिट रिपोर्ट में ज्यादा खुलासे करना अनिवार्य

वित्तीय अनुपातों पर टिप्पणी जैसे कुछ बदलावों से ऑडिटरों के काम में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी। लेकिन ऐसे बहुत से नए खुलासे हैं, जिनके लिए अतिरिक्त काम करना होगा। अब ऑडिटरों को कंपनी द्वारा बैंकों या वित्तीय संस्थानों को मुहैया कराए जाने वाले तिमाही नतीजों या विवरण का सत्यापन करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि वे कंपनी के खातों से मेल खाते हैं। जो अचल परिसंपत्तियां कंपनी के नाम नहीं हैं, उनकी जानकारी देने के लिए अब एक नया प्रारूप पहले से ज्यादा व्यापक है और इसके लिए ऑडिटरों को अतिरिक्त काम करना होगा।

कोरोनावायरस का असर बढ़ने से बॉन्ड चढ़े, लेकिन शेयरों में आई गिरावट

कोरोनावायरस (कोविड-19) संक्रमण पूरे यूरोप में फैल रहा है, जिससे पिछले चार सत्रों में सूचकांकों में गिरावट आई है। कोरोनावायरस की वजह से निश्चित आय योजनाओं और बॉन्डों में तेजी आई है, जिससे उनकी तरफ निवेशकों का रुझान बढ़ा है। बॉन्डों की कीमतों में बढ़ोतरी से प्रतिफल घटा है। पिछले कुछ कारोबारी सत्रों के दौरान अमेरिका के डॉलर सूचकांक ने बढ़त गंवाई है, लेकिन यह चीन में कोरोनावायरस के फैलने के बाद दिसंबर से अन्य मुद्राओं के मुकाबले मजबूत हो रहा है। अमेरिका का डॉलर सूचकांक इस मुद्रा की विश्व की अन्य प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले ताकत दिखाता है।

शेयर बाजार इन चिंताओं के कारण गिर रहे हैं कि कंपनियों को अस्थायी रूप से परिचालन बंद करना होगा, जिससे उनकी आमदनी प्रभावित हो रही है। इस बीच अमेरिका ने अपने यहां कोरोनावायरस संक्रमण फैलने की चेतावनी जारी की है। इससे इक्विटी सूचकांकों में और गिरावट आई है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जोर्जिबा ने रियाद में जी-20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक में कहा कि देशों को कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए, लेकिन फिर भी इसका नकारात्मक आर्थिक असर पड़ सकता है। जोर्जिबा ने कहा, 'निस्संदेह हम तेजी से सुधार की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन अनिश्चितता को देखते हुए ज्यादा खराब माहौल के लिए तैयार रहना उचित होगा।' **अनूप रॉय**

नुकसान का आकलन

	डॉलर के मुकाबले मुद्रा		10 साल के बॉन्ड का प्रतिफल (फीसदी)		इक्विटी सूचकांक	
	20 फरवरी	26 फरवरी	20 फरवरी	26 फरवरी	20 फरवरी	26 फरवरी
हॉन्ग-कॉन्ग	7.78	7.79	-	-	27,609	26,696
जापान	112.09	110.39	-0.04	-0.09	23,479	22,426
चीन	7.02	7.02	2.88	2.80	3,030	2,988
ब्रिटेन	0.78	0.77	0.58	0.51	7,437	6,983
भारत	71.66	71.62	6.42	6.34	41,170	40,169
सिंगापुर	1.40	1.40	1.66	-	3,199	3,129
द. कोरिया	1,198.37	1,216.95	1.53	-	2,196	2,077
यूरोजोन	0.93	0.92	-0.44	-0.51	3,823	3,551
द. अफ्रीका	15.13	15.24	8.86	8.85	52,033	48,582
ब्राजील	4.39	4.39	6.57	-	1,14,586	1,13,681
जर्मनी	0.93	0.92	-0.44	-0.51	3,823	3,551
अमेरिका	1.00	1.00	1.52	1.34	3,373	3,128

बीएस रिसर्च ब्यूरो द्वारा संकलित

अटक गई गोएयर की कतर उड़ान

कंपनी ने 19 मार्च से मुंबई-दोहा उड़ान शुरू करने की घोषणा की थी

अनीश फडणीस
मुंबई, 27 फरवरी

गोएयर की कतर के लिए पहली उड़ान शुरू करने की योजना अधर में लटक गई है। विमानन कंपनी ने इस महीने के प्रारंभ में 19 मार्च से मुंबई-दोहा उड़ान शुरू करने की घोषणा की थी और शुरुआत में 14,000 रुपये में आने-जाने की टिकट की पेशकश की थी।

ग्राहकों ने तेजी से टिकटें खरीदीं क्योंकि दोनों शहरों के बीच यात्रा के लिए किराया काफी सस्ता था। लेकिन अब विमानन कंपनी को अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है और इसने धीरे से इस उड़ान के लिए आरक्षण बंद कर दिया है। बुकिंग को स्थगित करने की वजह यह है कि कंपनी को गर्मियों में कतर के लिए ट्रैफिक अधिकार नहीं मिल पाए। सरकारें आपस में ट्रैफिक अधिकारों का लेनदेन करती हैं और अपनी-अपनी विमानन कंपनियों को आवंटित करती हैं ताकि वे नई उड़ानें शुरू कर सकें। पिछले साल नवंबर में गोएयर को कतर के लिए प्रति सप्ताह 1,300 सीट मिली थीं। इस तरह उसे रोजाना एक उड़ान की मंजूरी मिल गई। हालांकि यह सर्दियों के लिए अस्थायी आवंटन था, जो एयर इंडिया को आवंटित ट्रैफिक अधिकारों का उपयोग न होने पर आवंटित किया गया था। गोएयर ने ट्रैफिक अधिकारों की समयावधि बढ़ाने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय में आवेदन किया था और फिर मुंबई-दोहा उड़ान की घोषणा की।

लेकिन अब इसे अपनी उड़ान को टालने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है क्योंकि एयर इंडिया अपने बचे ट्रैफिक अधिकारों का इस्तेमाल करना और गर्मियों में दोहा के लिए और उड़ान शुरू करना चाहती है। गोएयर ने एक बयान में कहा, 'गोएयर को नवंबर 2019 में दोहा के लिए 2019 की सर्दियों (मार्च 2020 के अंत तक) के लिए अधिकार दिए गए थे, जो एयर इंडिया के इस्तेमाल नहीं हो रहे ट्रैफिक अधिकारों में से दिए गए थे। हम नए गंतव्य स्थल के लिए आवश्यक नियामकीय मंजूरियां हासिल करने पर काम कर रहे हैं। गोएयर मार्च 2020 के मध्य में परिचालन शुरू करने के लिए तैयार थी। गोएयर ने इन अधिकारों को 2020 की गर्मियों के लिए बढ़ाने की खातिर सरकार के पास आवेदन किया है। हमारा मानना है कि एयर इंडिया ने सरकार को सलाह दी है कि वह 2020 की गर्मियों में कतर के ट्रैफिक अधिकारों का पूर्ण इस्तेमाल कर लेगी। इसे मद्देनजर रखते हुए गोएयर ने आरक्षण या बुकिंग को स्थगित कर दिया गया है।'

एयर इंडिया और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के प्रवक्ताओं ने बिज़नेस स्टैंडर्ड के ईमेल का जवाब नहीं दिया। हालांकि विमानन उद्योग के अधिकारी एयर इंडिया की वित्तीय समस्याओं को देखते हुए उसकी योजनाओं को लेकर संदेह जता रहे हैं। पिछले साल अप्रैल में जेट एयरवेज के बंद होने के बाद सरकार ने उसके ट्रैफिक अधिकार एयर इंडिया और इंडिगो को आवंटित कर दिए थे।

एयर इंडिया के विनिवेश के शुरुआती सूचना दस्तावेज से पता चलता है कि नवंबर तक इस सरकारी विमानन कंपनी के पास कतर के लिए साप्ताहिक 10,395 सीट थीं। यह कतर की 5,562 सीटों का इस्तेमाल कर रही थी और 4,833 सीट बची हुई थीं। उसके बाद कंपनी ने मुंबई और त्रिची से दोहा के लिए नई उड़ानों की घोषणा की है। इनमें एक मुंबई से बोइंग 787 की उड़ान भी शामिल है, जो पिछले सप्ताह शुरू हुई है।

एयर इंडिया को गर्मियों में अपने ट्रैफिक अधिकारों का पूरा उपयोग करने के लिए हर सप्ताह दोहा के लिए उड़ान 13 से 18 बढ़ानी पड़ेंगी। अतिरिक्त उड़ानों की संख्या इस मार्ग पर लगाए जाने वाले विमानों के प्रकार पर निर्भर करेगी। पहले भी एयर इंडिया ने निजी विमानन कंपनियों के उसके अधिकारों का इस्तेमाल कर सेवाएं शुरू करने की योजनाओं का विरोध किया था। वर्ष 2018 में जेट एयरवेज ने एयर इंडिया के अनुपयोगी अधिकारों का इस्तेमाल करके लंदन की एक अन्य उड़ान शुरू करने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय से संपर्क साधा था। जेट को भीड़भाड़ वाले हीथ्रो हवाई अड्डे पर अपनी साझेदार विमानन कंपनियों से स्लॉट लिए थे।

खटाई में योजना

- **कंपनी को गर्मियों में कतर के लिए ट्रैफिक अधिकार नहीं मिल पाए**
- **शुरु में 14,000 रुपये में आने-जाने की बेची टिकट**
- **मगर अब चुपके से बंद कर दीं बुकिंग**

इन गर्मियों में नवी मुंबई में खुलेगा आइकिया का स्टोर

विवेट सुजन पिंटो
मुंबई, 27 फरवरी

फर्नीचर का खुदरा कारोबार करने वाली विश्व की सबसे बड़ी कंपनी आइकिया इस साल गर्मियों में नवी मुंबई में अपना स्टोर खोलेगी। कंपनी के प्रबंध निदेशक पीटर बेटजेल ने आज यह जानकारी देकर कंपनी की इस योजना को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लगा दिया है। वह मुंबई में आयोजित रिटेल लीडरशिप समिट में अलग से संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। दो साल पहले कंपनी के भारत के कारोबार का प्रभार अपने हाथ लेने वाले आइकिया के दिग्गज बेटजेल ने कहा कि मुंबई में कंपनी कम से कम एक और छोटा स्टोर खोलने पर काम कर रही है, जिससे शहर में कारोबार की संभावनाओं को विस्तार दिया जा सके। उन्होंने कहा कि यह मौजूदा कैलेंडर वर्ष के अंत तक किया जा सकता है।

उद्योग के सूत्रों ने कहा कि छोटे स्टोर का मकसद सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट और मुंबई के आवासीय इलाकों के ग्राहकों को आकर्षित करना है। छोटे स्टोर दक्षिण मुंबई और पश्चिमी और केंद्रीय उपनगरीय इलाकों में होंगे। नवी मुंबई में तुरभे में स्टोर खुलेगा।

ऑफलाइन छोटे व बड़े स्टोर के प्रारूप और ऑनलाइन स्टोर की शुरुआत वित्तीय राजधानी मुंबई में अगस्त 2019 में की गई थी। बेटजेल ने कहा यह भारत में पहला बाजार है, जहां खुदरा कारोबारी कंपनी का हाइब्रिड मॉडल होगा। आइकिया ने पहले संकेत दिया था कि वह भारत में हाइब्रिड रिटेल मॉडल अपनाएगी। इसके लिए कंपनी ने मुंबई के ई स्टोर के उद्घाटन के दौरान 1.5 अरब डॉलर निवेश की घोषणा की थी। साथ ही कंपनी ने कहा था कि भारत में बड़े आउटलेट खोलने के अलावा कंपनी ऑनलाइन व ऑफलाइन खुदरा पर ध्यान देगी। आइकिया को दुनिया भर में बड़े खुदरा स्टोर खोलने के लिए जाना जाता है। बेटजेल ने कहा कि हाइब्रिड रिटेल मॉडल का बेंगलूरु, दिल्ली और हैदराबाद में भी अनावरण किया जाएगा, जहां आइकिया ने अगस्त 2018 में भारत में पहला स्टोर खोला था। बेटजेल ने कहा कि उसके बाद हैदराबाद स्टोर में 60 लाख विजिटर आए और 400 करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार किया गया, जिसने बड़े आकार के स्टोर के हिसाब से खुदरा कारोबार में मानक स्थापित किया है।

हेलीकॉप्टर से ओरछा की सैर

मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग ओरछा में 6 मार्च से तीन दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम 'नमस्ते ओरछा' का आयोजन कर रहा है। विभाग की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इस दौरान पर्यटकों को निर्धारित शुल्क पर हेलीकॉप्टर से ओरछा नगरी का भ्रमण कराया जाएगा। इसके अलावा ग्वालियर से ओरछा आने जाने के लिए भी शुल्क पर हेलीकॉप्टर की सुविधा दी जाएगी। महोत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री कमलनाथ 6 मार्च को करेंगे। *बीएस*

राष्ट्रीय राजमार्गों का आवंटन 6 साल में सबसे सुस्त

मेघा मनचंदा
नई दिल्ली, 27 फरवरी

जमीन अधिग्रहण में देरी की वजह से राजमार्ग परियोजनाओं का आवंटन 6 साल में सबसे सुस्त हो गया है। इसकी वजह से अगले 2 साल तक निर्माण में सुस्ती बनी रहेगी।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) दोनों ही नई परियोजनाओं के आवंटन को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। एनएचएआई ने चालू वित्त वर्ष के दौरान 3,700 से 4,000 किलोमीटर परियोजनाएं आवंटित की है।

इक्रा के वाइस प्रेसीडेंट, एसोसिएट हेड-कॉर्पोरेट राजेश्वर बुर्ला ने आज कहा, 'सड़क परियोजनाओं का आवंटन पिछले 6 साल में सबसे सुस्त रहा है और वित्त वर्ष 2021 में भी स्थिरता बने रहने की उम्मीद है।'

अगले वित्त वर्ष में भी एनएचएआई के ऑर्डर बुक में स्थिरता बनी रहेगी। बहरहाल इस समय राजमार्ग परियोजनाओं पर काम सही चल रहा है। उन्होंने कहा, 'इसकी वजह यह है कि पिछले 4 साल के दौरान परियोजनाओं का आवंटन बहुत ज्यादा हुआ है, जिसकी वजह से कतार में परियोजनाएं ज्यादा हैं। उन पर इस समय काम हो रहा है।'

परियोजना आवंटन में सुस्ती आई है, जिसका असर 2022 में नजर आएगा क्योंकि 2019 से आवंटन सुस्त हुआ है। बहरहाल कुछ विशेषज्ञों को लगता है कि जमीन अधिग्रहण समस्या नहीं है, क्योंकि मुआवजा बेहद आकर्षक है।

पूर्व सड़क परिवहन सचिव विजय छिब्बर ने कहा कि परियोजनाओं के आवंटन में देरी की एक वजह मूल्यांकन प्रक्रिया भी थी। उन्होंने कहा, 'मुख्य रूप से धन की वजह से सड़क परियोजनाओं को लागू करने का काम प्रभावित हुआ है, क्योंकि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने सड़क परियोजनाओं का मूल्यांकन शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से देरी हो रही है।'

उन्होंने कहा कि एक बार जब राजमार्ग परियोजना वित्त मंत्रालय के पास मूल्यांकन के लिए चली जाती है तो उसमें 6 से 9 महीने की देरी हो जाती है क्योंकि इसे वित्त की स्थाई समिति के पास से होकर गुजरना होता है, जिसकी वजह से उसे लागू करने में देरी होती है।

कभी कभी परियोजनाओं को मंजूरी हासिल करने में मुश्किल होती है क्योंकि वित्त मंत्रालय तब तक मंजूरी नहीं देता, जब तक कि जमीन अधिग्रहण का 90 प्रतिशत काम पूरा न हो गया हो।

जमीन अधिग्रहण में हो रही देरी की वजह से आई सुस्ती

- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण दोनों का आवंटन रहा सुस्त
- वित्त मत्रालय के पास मूल्यांकन के लिए जाने की वजह से भी होती है परियोजनाओं में 6 से 9 महीने की देरी
- वित्त मंत्रालय जमीन अधिग्रहण का 90 प्रतिशत काम पूरा होने पर ही देता है काम शुरू करने को मंजूरी
- शेष अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया में लग जाते हैं 3 से 4 महीने

छिब्बर ने कहा, 'व्यावहारिक रूप से देखें तो 80 प्रतिशत जमीन पर कब्जा मिलने के बाद काम शुरू किया जा सकता है और शेष 10 प्रतिशत अधिग्रहण काम शुरू होने के बाद किया जा सकता है क्योंकि पूरी अधिग्रहण प्रक्रिया में 3 से 4 महीने लग जाते हैं। वहीं 80 प्रतिशत जमीन मिलने के बाद काम शुरू कर देने पर परियोजना में तेजी लाई जा सकती है।'

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पिछले साल संसद में कहा था कि सार्वजनिक उपयोग की जगहों के स्थानांतरण, पर्यावरण और वन संबंधी मंजूरी और रेलवे की सड़क उपरिगामी सेतु (आरओबी) और सड़क भूमिगत सेतु (आरयूबी) जैसे मसलों के कारण देरी हो रही है। उन्होंने कहा था कि अतिरिक्त सुविधाओं के लिए जनता के विरोध प्रदर्शन, पंचाट और ठेकेदार के साथ ठेके संबंधी विवाद, भूमि अधिग्रहण में आने वाली कठिनाइयों, ठेकेदारों के खराब प्रदर्शन की वजह से भी निर्माण कार्य प्रभावित होता है।

मंत्री के मुताबिक सरकार ने सड़क परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण में तेजी लाने के लिए कदम उठाए हैं। मौजूदा सर्किल दर से ज्यादा मूल्य या पिछले तीन साल के दौरान जमीन की बिक्री संबंधी लेन देन के औसत से 50 प्रतिशत ज्यादा मूल्य दिए जाने का प्रावधान है।

केंद्र सरकार ने जमीन अधिग्रहण संबंधी मसलों के समाधान के लिए राज्य के मुख्य सचिवों के अधीन समिति का गठन किया है। तेजी से फैसले करने के लिए क्षेत्रीय अधिकारियों को अधिकार दिया गया है। अन्य मंत्रालयों व राज्य सरकारों के साथ बेहतर तालमेल के लिए केंद्र सरकार नियमित समीक्षा करती है।

एनसीएईआर ने जारी किया भूमि रिकॉर्ड सूचकांक

बीएस संवाददाता
मुंबई, 27 फरवरी

राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर) ने नया एनसीएईआ भूमि रिकॉर्ड एवं सेवा सूचकांक (एन-एलआरएसआई 2020) जारी किया है। एन-एलआरएसआई में भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण और भारत के राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में इन भूमिक रिकॉर्डों की गुणवत्ता दी गई है। एन-एलआरएसआई 2020 में मध्य प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु शीर्ष राज्य बनकर उभरे हैं। एनसीएईआर संपत्ति अधिकार शोध कंसोर्टियम का हिस्सा है। यह ओमिडयार नेटवर्क इंडिया के अनुदान से चलने वाली एक बहु संस्था शोध कंसोर्टियम है। प्रॉपर्टी राइट रिसर्च कंसोर्टियम का ध्यान जमीन के अधिकार, आवास व अन्य संपत्तियों पर शोध करने व साक्ष्य जुटाने पर होता है।

दिल्ली में पेशेवरों के लिए रेडबस की पूल सर्विस

नेहा अलावधी
नई दिल्ली, 27 फरवरी

ऑनलाइन बस टिकटिंग प्लेटफॉर्म रेडबस ने आज दिल्ली में कार पूलिंग और बाइक पूलिंग सेवा की शुरुआत की है। इसमें राष्ट्रीय राजधानी में कार्यालय जाने वालों को अपनी निजी कार और बाइक पर दूसरों को सवारी की सुविधा देने और दूसरों से सवारी की सुविधा लेने की सहूलियत होगी। यह सेवा आरपूल नाम से शुरू की गई है, जिसका लाभ रेडबस मोबाइल ऐप के माध्यम से सीधे उठाया जा सकता है।

टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के मुताबिक दिल्ली वालों ने 2019 में व्यस्त समय के दौरान साल भर में एक सप्ताह ट्रैफिक जाम में बिताए हैं, वहीं लॉस बेगास में 3 दिन ट्रैफिक में बिताने पड़े हैं, जबकि इस अमेरिकी शहर में लोगों ने अपने वाहन से 6 गुना ज्यादा यात्राएं की हैं।

दिल्ली में 2018 में सड़कों पर 1.12 करोड़ वाहन थे, जिसमें पहले के 5 वर्षों की तुलना में औसतन करीब 7.6 प्रतिशत की दर से बढ़ोतरी हुई है।

बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की ओर से प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक यातायात जाम की वजह से शहर को जीडीपी का करीब 12 प्रतिशत या करीब 9.6 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा है।

शेयर्ड इकॉनमी में भारत में आया मोटा निवेश

नेहा अलावधी
नई दिल्ली, 27 फरवरी

भारत की शेयर्ड इकॉनमी ने अब तक निवेशों में करीब 3.7 अरब डॉलर आकर्षित किया है। यह जानकारी बूटिक निवेश बैंक मैपल कैपिटल एडवाइजर्स की ओर से शेयर्ड इकॉनोमी-इंडिया स्टोरी नाम से जारी की गई रिपोर्ट में सामने आई है।

रिपोर्ट में शेयर्ड इकॉनमी के चार प्रमुख क्षेत्रों साथ साथ रहने (को-लिविंग), साथ साथ काम करने (को-वर्किंग), साझेदारी में परिवहन करने और फर्नीचर रेंटल पर प्रभाव का अध्ययन किया गया है।

मैपल कैपिटल एडवाइजर्स के प्रबंध निदेशक पंकज कर्ना ने कहा, 'भारत शेयर्ड इकॉनमी क्रांति के करीब है। बाजार हिस्सेदारी को हासिल करने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहीं अंतरराष्ट्रीय कंपनियों और घरेलू स्टार्टअप दोनों के साथ हम इस खंड में पहले से ही असाधारण वृद्धि दर्ज कर रहे हैं। भले ही यह क्षेत्र फिलहाल उदीयमान है लेकिन इसमें 3.7 अरब डॉलर का निवेश हो चुका है और हम उम्मीद करते हैं कि बढ़ती मांग और इकाई अर्थव्यवस्थाओं के कारण यहां से इसमें और अधिक तेजी आएगी।'

इस रुझान को मोबाइल के तेज प्रसार, युवाओं की अधिक आबादी और महत्त्वाकांक्षी जनसंख्या के साथ साथ एशिया में साझी संपत्तियों का उपयोग करने की उच्च आंकाक्षा से मदद मिल रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन मामलों में एशिया के रुझान की झलक भारत में भी दिखती है लिहाजा इसमें तेज वृद्धि नजर आ रही है और भारत में भी साझी सेवाओं को अपनाने का रुझान बढ़ा है।

सह कार्य स्थल का बाजार फिलहाल 50 करोड़ डॉलर के पार जा चुका है और भारत की शेयर्ड इकॉनमी के क्षेत्र में यह सर्वाधिक तेजी से बढ़ रहे खंडों में से एक है।

बहुत तेजी से बढ़ रहे क्षेत्र के तौर पर इस खंड के पास भारत में शीर्ष सात शहरों में 52.5 करोड़ वर्गफुट के वाणिज्यिक स्थल में से 80 से 90 लाख वर्गफुट जगह है और दो अंकों की मजबूत वृद्धि का प्रदर्शन कर रहा है।

को-लिविंग का क्षेत्र करीब 40 करोड़ डॉलर का है और तेजी से फैल रहा है। यह विशेष तौर पर छात्रों और युवा पेशेवरों की जरूरतें पूरी करता है। इस क्षेत्र में दो लाख से अधिक बिस्तर मौजूद हैं।

को-लिविंग में स्वीकार्यता और रहने की लागत में कमी इस क्षेत्र के प्रमुख उत्प्रेरक हैं जिनके दम पर यह दो अंक में वृद्धि कर रहा है।

शेयर्ड इकॉनमी का सबसे बड़ा हिस्सा शेयर्ड मोबिलिटी यानी साझेदारी में परिवहन करना है। इसका बाजार आकार 63 करोड़ डॉलर से अधिक का है जिसमें सवारी कैब प्लेटफॉर्मों का दबदबा है।

युवाओं की अहम भूमिका

- बूटिक निवेश बैंक मैपल कैपिटल एडवाइजर्स की रिपोर्ट के मुताबिक शेयर्ड इकॉनमी ने अब तक करीब 3.7 अरब डॉलर आकर्षित किया
- रिपोर्ट में चार प्रमुख क्षेत्रों- को-लिविंग, को-वर्किंग, साझेदारी में परिवहन करने और फर्नीचर रेंटल का अध्ययन किया गया है

हिंसा पीड़ित कारोबारियों को भी मिलेगा मुआवजा

बीएस संवाददाता
नई दिल्ली, 27 फरवरी

दिल्ली में हिंसक प्रदर्शनों से कारोबारियों को भी काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कारोबारियों को भी मुआवजा देने का ऐलान किया है। सरकार इन कारोबारियों को रियायती दर पर कर्ज भी मुहैया कराने जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन कारोबारियों की दुकानों का बीमा है, उनके निपटान के लिए दिल्ली वित्त विभाग को निर्देश दिए हैं। सरकार हिंसा प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री भी बांटेगी।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज हिंसा में जान गवाने वालों को 10 लाख रुपये और घायलों को 5 लाख रुपये तक मुआवजे की घोषणा की। इसके साथ ही जिन कारोबारियों की दुकानें जल गई उन्हें 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा, अगर उनकी दुकान का बीमा नहीं है। मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग को हिंसा में क्षतिग्रस्त बीमा वाली दुकानों और वाहनों के बीमा दावों के तुरंत निपटान हेतु बीमा कंपनियों से समझौता कर कैम्प लगाने के निर्देश दिए। दिल्ली वित्त निगम को भी दुकानें जलने के कारण नुकसान झेलने वाले कारोबारियों को रियायती दर कर्ज मुहैया कराने के लिए योजना बनाने को कहा। दिल्ली सरकार रिक्शा के जलने पर 25 हजार, ई-रिक्शा के जलने पर 50 हजार और घर के जलने पर 5 लाख रुपये तक मुआवजा देगी। सरकार हिंसा प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री भी बांटेगी।

दिल्ली सरकार के कारोबारियों की मदद के फैसले से पहले कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने हिंसा में नुकसान झेलने वाले कारोबारियों को मुआवजा और केंद्रीय गृहमंत्री से सुरक्षा देने की मांग की थी।

भारतीय उद्योग व्यापार मंडल दिल्ली इकाई के महामंत्री हेमंत गुप्ता कहते हैं कि व्यापार का केंद्र पुरानी दिल्ली के बाजारों में बाहरी राज्यों के कारोबारी माल भेजने में भी फिलहाल कतरा रहे हैं।

अमेरिका से कारोबारी समझौते पर सुस्त चाल चलेगा भारत

मुक्त व्यापार समझौते के लिए बेहतर छूट की पेशकश तैयार करने के बाद बैठक करेंगे भारत और अमेरिका

शुभायन चक्रवर्ती
नई दिल्ली, 27 फरवरी

अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के द्विपक्षीय दौरे में कारोबारी समझौते को लेकर कोई स्पष्ट समय सीमा न तय होने के बाद भारत ने अब बातचीत के मोर्चे पर धीमी रफ्तार से चलने का लक्ष्य रखा है। दोनों पक्ष सीमित कारोबारी समझौते के बजाय अब समग्र मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) करना चाहते हैं जिसमें व्यापक संभावनाएं हों।

दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारी इस बात पर सहमत हुए हैं कि बेहतर छूट की पेशकश के साथ समझौते का खाका तैयार किया जाए, जिसमें मेडिकल उपकरण, कृषि और महंगे तकनीकी सामान सहित ज्यादातर मसले शामिल हों। भारत के दूसरे सबसे बड़े कारोबारी साझेदार के साथ बातचीत में अमेरिका के जनरलाइज्ड सिस्टम आफ प्रेफरेंसेज (जीएसपी) योजना और पारस्परिक शुल्क जैसी कारोबारी अवधारणाएं शामिल होंगी, जिसमें तमाम क्षेत्र शामिल होंगे।

भारत का अमेरिका के साथ कारोबार

घटते व्यापार अधिशेष से कारोबारी समझौते पर पड़ सकता है असर

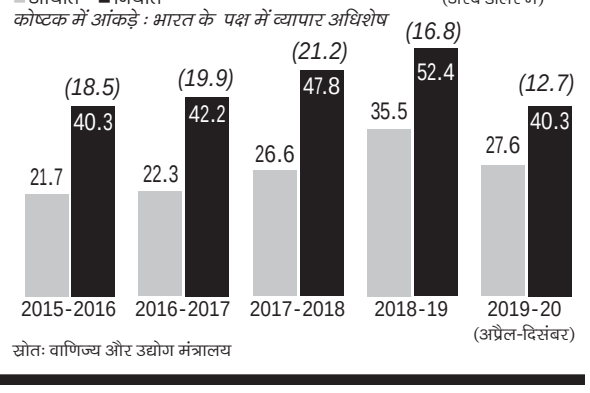

स्रोतः वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

मंगलवार को ट्रंप ने कहा था कि भारत के साथ समग्र कारोबार समझौते को अंतिम रूप देने में पहले लगाए गए अनुमान की तुलना में अभी बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। उन्होंने कहा कि यह इस साल के आखिर के पहले होने की संभावना नहीं है। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि कारोबारी बाधाएं खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप के उच्च स्तरीय दौरों की असफलता के बाद अब सरकार चाहती है कि समय लेकर बातचीत का बेहतर प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह समझौता इसलिए नहीं हो सका कि दोनों देशों की ओर से की जा रही प्रमुख मांगें पूरी नहीं की जा सकीं और अब हमें समझौते का खाका तैयार करने के लिए फिर से बैठने की जरूरत है। बहरहाल भारत वाणिज्य अधिकारियों के अगले दौरे के लिए अमेरिका के साथ जल्द ही बातचीत शुरू करेगा।

सरकार के वरिष्ठ अधिकारी अमेरिका के वाणिज्य मंत्री रॉबर्ट लाइटहाइजर के साथ बातचीत करेंगे, जिन्होंने अचानक दिल्ली की यात्रा रद्द कर दी थी और इसकी वजह से समझौता नहीं हो सका। लाइटहाइजर को कारोबार के मामले में ट्रंप का दाहिना हाथ माना जाता है। उम्मीद की जा रही थी कि वह संभावित कारोबारी समझौते के मद्देनजर ट्रंप के दल के साथ भारत आएंगे। उनके कार्यालय ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया कि वह इस बार क्यों उपस्थित नहीं रहे, वहीं राजनयिक सूत्रों ने कहा कि लाइटहाइजर ऐसे किसी समझौते के साथ अपना नाम नहीं जोड़ना चाहते थे, जो आधा अधूरा हो।

विश्व व्यापार संगठन में चली लड़ाई के बाद भारत को निर्यात संवर्धन योजनाओं का लाभ बंद करने में लाइटहाइजर की प्रमुख भूमिका थी।

अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की कि भारत ने छोटे समझौते पर हस्ताक्षर की पेशकश की थी, जो कृषि वस्तुओं पर केंद्रित था। वाणिज्य विभाग के एक अधिकारी ने कहा, 'कृषि उत्पादों पर शुल्क को लेकर बातचीत खुली थी और यह सुझाव दिया गया था कि इससे सीमित कारोबारी सहयोग समझौता हो सकता है और दोनों नेता संयुक्त बयान दे सकते हैं।'

उन्होंने कहा कि इसे इस रूप में देखा जा रहा था कि भारत बादाम, अखरोट, सेब और शराब जैसे महंगे कृषि उत्पादों से क्रमिक रूप से शुल्क वापस ले सकता है। भारत ने पिछले साल इन कृषि उत्पादों सहित 29 वस्तुओं पर 50 प्रतिशत तक आयात शुल्क लगा किया था। अमेरिकी किसान ट्रंप के प्रमुख समर्थक हैं, जिन्होंने ट्रंप सरकार द्वारा एकतरफा कर बढ़ाने के बाद अपने प्रमुख बाजार गंवा दिए, क्योंकि जवाब में अन्य देशों ने भी अमेरिका से महंगे उत्पादों के आयात पर कर बढ़ा दिया है।

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 13 अंक 11

फसल बीमा सुधार

सरकार ने अपनी शीर्ष फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) में सुधार के उपायों का जो पैकेज घोषित किया है वह किसानों की मदद के बजाय शायद उनका नुकसान अधिक कर दे। इसमें दो राय नहीं कि पैकेज में ऐसे सकारात्मक तत्त्व शामिल हैं जो किसानों को लाभ पहुंचा सकते हैं लेकिन कई अन्य उपाय ऐसे भी हैं जो शायद बीमा कंपनियों अथवा राज्य सरकारों को ठीक न लगें।

एक बेहतर बात यह है कि फसल बीमा को सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक बना दिया गया है। फिलहाल बैंक ऋण लेने वाले सभी किसानों के लिए यह बीमा अनिवार्य है जबकि अन्य लोगों के लिए यह स्वैच्छिक है। इसका एक अन्य स्वागतयोग्य गुण है नुकसान के आकलन को तयशुदा में पूरा करने की प्रक्रिया को तार्किक बनाना। यदि राज्य सरकार फसल कटाई के अनुभव आधारित आंकड़े तय अवधि में देने में नाकाम रहती है तो बीमा कंपनियों को दावों का निस्तारण प्रारंभिक अनुमान के आधार पर करने की इजाजत देना बेहतर होगा। ऐसा करने से दावों के निस्तारण में होने वाली अनावश्यक देरी कम होगी। इस योजना के खिलाफ दावा निपटाने में होने वाली देरी भी प्रमुख शिकायत है।

बहरहाल, पीएमएफबीवाई का एक नकारात्मक पहलू ज्यादा चिंतित करने वाला है। नए डिजाइन में इस योजना के उस विशिष्ट गुण को मंद कर दिया गया है जो इसे अन्य कृषि बीमा योजनाओं से अलग करता है। इसमें वे तमाम जोखिम शामिल हैं जिनके बारे में सोचा जा सकता है। इसमें बुआई के पहले से फसल कटाई के बाद तक के सारे नुकसान शामिल थे। राज्यों को यह स्वायत्तता देने का भी प्रस्ताव है कि वे इस योजना के तहत कवर की जाने वाली बीमारियों का चयन करें। ऐसे में उन्हें यह इजाजत होगी कि वे उन किसानों को राहत प्रदान कर सकें जो सूखे के कारण फसल बुआई न कर सके हों या जिनकी खेतों में खड़ी फसल को नुकसान पहुंचा हो। इससे किसानों के लिए योजना की उपयोगिता कम होती है।

इसके अलावा नए मानक फसल बीमा प्रीमियम पर केंद्रीय सब्सिडी को असिंचित क्षेत्र में 30 फीसदी और सिंचित क्षेत्र में 25 फीसदी पर सीमित करते हैं। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के लिए यह 90 फीसदी होगा। केंद्रीय सब्सिडी और बीमा कंपनी द्वारा उल्लिखित वास्तविक प्रीमियम का अंतर पूरी तरह राज्य सरकार द्वारा चुकता किया जाएगा। इससे पहले कुल सब्सिडी केंद्र और राज्य सरकारें समान मात्रा में साझा करती थीं। ऐसे में केंद्र का वित्तीय बोझ कम होगा लेकिन राज्यों पर बोझ बढ़ेगा जो शायद उन्हें स्वीकार्य न हो। बीमा कंपनियां भी उतना ऊंचा प्रीमियम नहीं ले पाएंगी जितना कि वे अब तक वसूल रही थीं। बीमारियों की आशंका वाले शुष्क इलाकों में जहां प्राय: सूखा पड़ता रहता है वहां वे 75 प्रतिशत तक प्रीमियम लेती रही हैं। चूंकि राज्य सरकारें इस उद्देश्य के लिए अधिक राशि देना नहीं चाहेंगी इसलिए बीमाकर्ता को या तो कम प्रीमियम लेना होगा या फिर वह योजना से बाहर हो जाएगी। दूसरे विकल्प की संभावना अधिक है क्योंकि चार निजी बीमा कंपनियां पहले ही पीएमएफबीवाई से बाहर निकल चुकी हैं। उनका कहना है कि कृषि बीमा मुनाफे का सौदा नहीं है।

इसी प्रकार तीन राज्यों ने पीएमएफबीवाई का क्रियान्वयन रोक दिया है। इसके अलावा भी कई राज्यों ने केंद्र को यह नोटिस दिया है कि वे भी ऐसा ही करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्रालय भी इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं नजर आ रहा है। उसने पहले ही यह घोषणा कर दी है कि वह राज्यों के लिए विशेष तौर पर तैयार वैकल्पिक कार्यक्रम पेश करेगी। अब तक जितने भी फसल बीमा मॉडल आजमाए गए हैं उनके कमजोर ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए गैर बीमा आधारित जोखिम बचाव उपायों की आवश्यकता है।

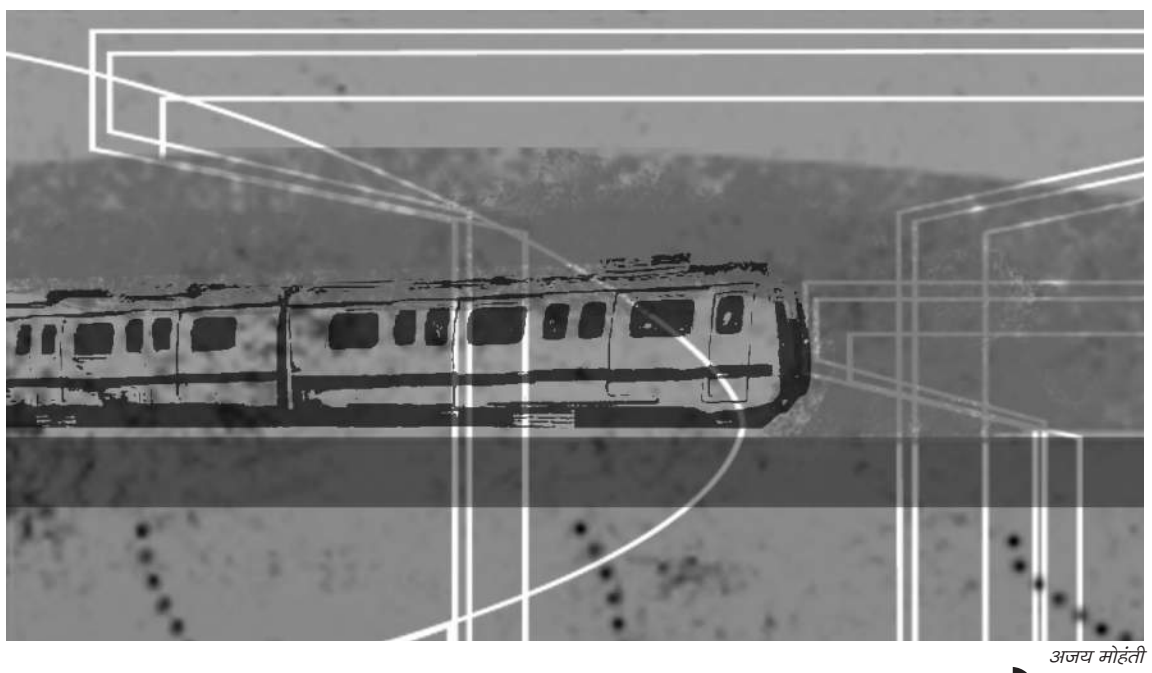

अजय मोहंती

ब्रिटेन के एनआईसी जैसे निकाय की जरूरत

भारतीय ढांचागत क्षेत्र में नई ऊर्जा भरने के लिए ब्रिटेन के एनआईसी जैसे नियामकीय संस्थान के गठन की जरूरत है। इसकी अहमियत को रेखांकित कर रहे हैं **विनायक चटर्जी**

तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 10 जुलाई, 2014 को संसद में अपना पहला बजट भाषण देते हुए खंड पांच के पैराग्राफ 110 में ढांचागत क्षेत्र का जिक्र किया था। जेटली ने कहा था, 'भारत दुनिया में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) का सबसे बड़ा बाजार बनकर उभरा है। इस समय 900 से अधिक परियोजनाएं विकास के विभिन्न चरणों में हैं।

पीपीपी के जरिये हवाईअड्डों, बंदरगाहों और राजमार्गों के कुछ शानदार ढांचे तैयार किए गए हैं। लेकिन हमने पीपीपी प्रारूप में कुछ खामियां देखी हैं, अनुबंध प्रावधानों में कठोरता, अनुबंध बनाने के परिष्कृत एवं उन्नत मॉडल तैयार करने और विवाद निपटान की त्वरित व्यवस्था के विकास की जरूरत को महसूस किया है। भारत में पीपीपी करारों को मुख्यधारा में लाने के लिए 500 करोड़ रुपये के कोष से 3पी इंडिया नाम का संस्थागत आधार तैयार किया जाएगा।'

26 मई, 2015 :

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार ने पूर्व वित्त सचिव विजय केलकर की अध्यक्षता में एक नौ सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति ने 19 नवंबर, 2015 को 'ढांचागत विकास के पीपीपी मॉडल की समीक्षा एवं पुनर्जीवन' पर केंद्रित अपनी रिपोर्ट पेश की। समिति ने 3पी इंडिया के गठन की पुरजोर वकालत करते हुए कहा कि यह संस्था पीपीपी में उत्कृष्टता केंद्र के तौर पर काम करने के अलावा क्षमता निर्माण से जुड़े शोध, समीक्षा एवं गतिविधियों का खाका पेश करेगी। केलकर समिति ने पीपीपी ढांचे के तीन प्रमुख स्तंभों- शासन, संस्थान और क्षमता को और मजबूत करने की जरूरत बताई ताकि क्रियान्वयन के नए दौर के लिए मजबूत ढांचा खड़ा किया जा सके।

31 दिसंबर, 2019 :

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2019-25 के लिए राष्ट्रीय ढांचा पाइपलाइन (एनआईपी) पर गठित कार्यबल की रिपोर्ट जारी की। उन्होंने कहा, 'वर्ष 2024-25 तक पांच लाख करोड़ रुपये का जीडीपी लक्ष्य हासिल करने के लिए भारत को इस अवधि में ढांचागत क्षेत्र पर करीब 1.4 लाख करोड़ रुपये खर्च करने की जरूरत है। चुनौती ढांचागत निवेश पर सालाना खर्च बढ़ाने की है ताकि ढांचे का अभाव भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि पर बाध्यकारी अवरोध न बने।'

काफी पहले यह माना जा चुका है कि आर्थिक वृद्धि के प्रमुख वाहक के तौर पर ढांचागत एजेंडे को जोर-शोर से बढ़ाया जाए। एक दूरदृष्टि वाली एक परियोजना-पाइपलाइन की रूपरेखा और उसका वित्तपोषण करना ही काफी नहीं है, जरूरी संस्थागत क्षमता भी होनी चाहिए। ब्रिटेन में अक्टूबर 2015 में गठित राष्ट्रीय ढांचागत आयोग (एनआईसी) भी भारत के लिए कुछ सबक समेटे हुए है।

ब्रिटेन के एनआईसी का चार्टर क्या है?

ब्रिटेन के वित्त विभाग के मातहत एक स्वतंत्र एजेंसी के तौर पर संचालित होने वाली एनआईसी देश की दीर्घावधि ढांचागत प्राथमिकताओं पर केंद्रित थिंक-टैंक के तौर पर काम करती है। यह ढांचागत क्षेत्र से जुड़ी चुनौतियों और रणनीति पर सरकार को सलाह एवं अनुशंसा भी देती है। इसका अपना एक सचिवालय है जिसमें करीब 50 कर्मचारियों का नेतृत्व मुख्य कार्याधिकारी (सीईओ) करता है।

एनआईसी लंबी अवधि का नजरिया लेकर चलता है। यह हरेक संसद का कार्यकाल खत्म होने पर राष्ट्रीय ढांचागत आकलन प्रकाशित करता है और देश को 30 वर्ष तक की अवधि में पड़ने वाली ढांचागत जरूरतें तय करने के साथ ही इन जरूरतों को पूरा करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों की अनुशंसा भी सरकार को करता है।

लेकिन यह आयोग तात्कालिक जरूरतों पर भी नजर रखता है। विशुद्ध रूप से दीर्घकालिक नजरिया रखने में जोखिम यह है कि अगले 30 साल नहीं, बल्कि पांच साल को केंद्र में रखने वाली सरकार इसके सुझावों को नजरअंदाज ही कर दे। इसी वजह से आयोग तात्कालिक रूप से अहम ढांचागत जरूरतों पर क्षेत्र-केंद्रित रिपोर्ट जारी करता है। यह एक संकीर्ण क्षेत्र केंद्रण से परे है। मसलन, परिवहन क्षेत्र में यह बहुआयामी संदर्भों में समाधानों का परीक्षण करता है जिसमें सड़क, रेल और मेट्रो परिवहन के बीच अंतर्निर्भरता पर ध्यान दिया जाता है।

एनआईसी चार्टर सरकार के साथ संबंध, अधिकार और उत्तरदायित्व स्पष्ट करता है। सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह एनआईसी के दिए सुझावों पर कदम उठाए और कारण सहित यह बताए कि किस सुझाव को स्वीकार करना है और किसे खारिज? एनआईसी इन सुझावों पर प्रगति की निगरानी करता है। यह एक वार्षिक निगरानी रिपोर्ट प्रकाशित करता है जो इसके पुराने सुझावों पर हुई सरकारी प्रगति पर नजर रखती है। इस तरह से यह आकांक्षाओं एवं वास्तविक उपलब्धियों के बीच के फासले पर एक वस्तुस्थिति परीक्षण के तौर पर काम करता है। यह दूसरे संस्थानों के साथ पुल के तौर पर भी काम करता है। एनआईसी के चार्टर में कहा गया है कि इसे नीति-निर्माताओं, ढांचागत विशेषज्ञों और क्षेत्र नियामकों जैसे दूसरे हितधारकों के संपर्क में भी रहना चाहिए। यह अहम है क्योंकि भारत में एनआईसी से मिलते-जुलते संस्थानों के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि मंत्रालय के कर्ताधर्ता अपनी जमीन बचाए रखने के लिए बाहरी संस्थानों से मिले सुझावों को स्वीकार करने में आनाकानी करते हैं।

एनआईसी को आम जनता से संवाद रखना होगा। इसका चार्टर के मुताबिक आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करते समय आम लोगों से संपर्क करना होगा। जनता के ही सबसे बड़ा उपभोक्ता और अधिकांश ढांचागत परियोजनाओं का उपयोगकर्ता होने से यह कार्य सहमति-निर्माण के लिए बेहद अहम है। एनआईसी वित्तीय रूप से स्वतंत्र संस्था है। भले ही यह तकनीकी तौर पर वित्त विभाग के अधीन है लेकिन सरकार के साथ 'बहुवर्षीय वित्तीय समाधान' के जरिये इसे फंड मिलता है। ऐसा होने से आयोग को हर साल बजट में अपने लिए प्रावधान की फिक्र करने के बजाय एक साथ कई वर्षों के लिए फंड मिल जाता है।

इसी तरह इसकी परिचालनात्मक स्वतंत्रता का मुद्दा है। इसका चार्टर यह स्पष्ट करता है कि 'इसे स्वतंत्र ढंग से कार्यक्रम बनाने, कार्य-प्रणाली और अनुशंसाएं करने का पूर्ण विवेकाधिकार है। इसके अलावा अपनी रिपोर्ट एवं सार्वजनिक बयानों की सामग्री में भी उसे स्वतंत्रता होती है।'

एनआईसी को प्रतिभाशाली लोगों को साथ जोड़ने की क्षमता है। भारतीय संस्थानों की एक कमजोरी यह रही है कि वे सेवानिवृत्त अफसरशाहों के लिए शरणगाह बनकर रह गए हैं। एनआईसी न केवल लोकसेवकों बल्कि ढांचागत क्षेत्र, स्थानीय सरकारों और नियामकों से भी पेशेवरों को अपने साथ जोड़ता है।

भारतीय ढांचागत क्षेत्र में नई ऊर्जा भरना ब्रिटेन के एनआईसी जैसे संस्थान के गठन पर काफी हद तक निर्भर करता है। ब्रिटेन का एनआईसी जिन सिद्धांतों पर बना था वह इसकी राह दिखाता है।

(लेखक ढांचागत परामर्श फर्म फीडबैक इन्फ्रा के चेयरमैन हैं)

सर्वोच्च न्यायालय की घोषणा बैंक अधिकारियों की राहत

सर्वोच्च न्यायालय ने इस महीने के आरंभ में एक महत्त्वपूर्ण घोषणा की जो वरिष्ठ बैंक अधिकारियों को बहु प्रतीक्षित राहत प्रदान करती है। ये अधिकारी हमेशा इस आशंका के साये में जीते थे कि उन्होंने जिन कंपनियों को ऋण दिया है, यदि वे जांच के दायरे में आती हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 339 में उन लोगों को व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह ठहराने की बात शामिल है जो किसी कंपनी के कारोबार को चलाने के भागीदार थे और जिनके बारे में ऐसा पता चलता है कि उन्होंने बिना किसी जवाबदेही के कंपनी के ऋणदाताओं को ठगा तो उन पर कार्रवाई की जा सकती है। यह बात कंपनी के तमाम ऋण और देनदारियों पर लागू होती है। इस शक्ति के विरुद्ध जांच परख की व्यवस्था यह है कि इससे जुड़ा निर्णय केवल राष्ट्रीय कंपनी लॉ पंचाट ही ले सकता है। यदि इस अधिकार का इस्तेमाल किया जाता है और पंचाट यह घोषणा करता है कि किसी व्यक्ति को इस प्रावधान के अधीन लाया जाए तो जवाबदेही तय करने के लिए जरूरी निर्देश जारी किए जा सकते हैं।

नीरव मोदी के मामले में इस अधिकार का इस्तेमाल ऋणदाताओं से संबंधित प्रक्रियाओं में किया गया, यानी नीरव मोदी द्वारा प्रवर्तित कंपनी, न कि बैंक से संबंधित प्रक्रियाएं। कंपनी मामलों के मंत्रालय ने जनहित में दमन और कुप्रबंधन का मामला उठाया और उन प्रक्रियाओं के दौरान पंजाब नैशनल बैंक के चेयरमैन (एक वर्ष नौ माह तक चेयरमैन रहे) की परिसंपत्तियां कुर्क कर ली गईं। राष्ट्रीय कंपनी लॉ अपील पंचाट भी इस बात पर सहमत हो गया कि बैंक के चेयरमैन की परिसंपत्तियों को ऐसे अधिकार का प्रयोग करके कुर्क किया जा सकता है। वह केवल अपनी आजीविका के लिए प्रतिमाह एक लाख रुपये तक निकाल सकते थे। इसका आधार यह था कि केंद्रीय जांच ब्यूरो ने बैंक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करते समय चेयरमैन को आरोपित बनाया था और कहा था कि उन्होंने उचित सतर्कता नहीं बरती।

बाअदब

सोमशेखर सुंदरेशन

सीबीआई जांच का निर्णय तो मामले की वरीयता पर निर्धारित होगा लेकिन किसी कर्जदार कंपनी में हुई गड़बड़ी के मामले में बैंक अधिकारियों को अपराधी मानना बैंक अधिकारियों के सामान्य कामकाज को प्रभावित करने के लिए काफी है।

सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि धारा 339 की व्यापक शक्तियों और उसके दायरे का लक्ष्य है उस कंपनी के हितों का बचाव करना जहां कुप्रबंधन हुआ हो। जिस कारोबार के आचरण का उल्लेख किया गया है वह संबंधित कंपनी का कारोबार है न कि अन्य कंपनियों और व्यक्तियों का। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा था, 'यह स्पष्ट है कि इन धाराओं के अधीन आने वाली शक्तियों का पालन ऐसे आदेश में नहीं हो सकता जहां कोई ऐसा व्यक्ति शामिल हो जो अन्य संस्थानों का भी प्रमुख हो और वह या उसकी संपत्ति कुर्क की गई हो।'

कर्जदार की ओर से धोखाधड़ी के मामलों में बैंक अधिकारियों को घसीटे जाने के कारण बैंक अधिकारी ऋण संबंधी निर्णय लेने से बचते हैं। बैंक अधिकारियों के मन में समाया डर ऋण विस्तार में कमी के लिए किस हद तक जिम्मेदार है इस बारे में ठीक-ठीक तो कुछ नहीं कहा जा सकता है लेकिन सच यही है कि बैंक अधिकारी इस बात को लेकर घबराते हैं कि कहीं आधी रात को जांच अधिकारी उनके दरवाजे पर दस्तक न दे दें। उनके द्वारा सद्भावना में दिए गए ऋण के मामले कहीं धोखाधड़ी न साबित हों। कंपनी अधिनियम की धारा 339 की शक्तियों का प्रयोग एक नई विशेषता थी जिसने बैंक अधिकारियों के बीच भय और आशंका बढ़ाने का काम किया। हम जिस मामले की बात कर रहे हैं उसमें शामिल व्यक्ति करीब दो वर्ष तक बैंक का चेयरमैन था।

सीबीआई यह जांच कर सकती है कि मामले में कोई आपराधिक पहलू था या नहीं और क्या अंतत: उसे आपराधिक जांच प्रक्रिया में सबूतों से जूझना होगा। बहरहाल, आततायी और पीड़ित की भूमिका को आपस में बदला नहीं जा सकता है। जब कोई कर्जदार कंपनी बैंक के साथ धोखाधड़ी करती है तो बहुत संभव है कि कंपनी का भी कुप्रबंधन हो। बैंक धोखाधड़ी के मामले में कर्जदार अपराधी है और बैंक पीड़ित। कंपनी के कुप्रबंधन की स्थिति में ऐसा नहीं होगा कि बैंक अधिकारियों ने कंपनी को धोखा दे रहे हों और उन्होंने कंपनी से पैसे निकाले हों। उन प्रक्रियाओं में पीड़ित, अपराधी नहीं हो सकता।

जब धोखाधड़ी के किसी मामले का पता चलता है, वह भी किसी बड़ी धोखाधड़ी का तो ढेर सारा शोरशराबा होता है। ऐसे में कानून में उल्लिखित शब्दों की भी पर्याप्त व्याख्या होगी। सीबीआई जांच का निर्णय तो मामले की वरीयता पर निर्धारित होगा लेकिन किसी कर्जदार कंपनी में हुई गड़बड़ी के मामले में बैंक अधिकारियों को अपराधी मानना बैंक अधिकारियों के सामान्य कामकाज को प्रभावित करने के लिए काफी है। यह अच्छी बात है कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में अपनी बात सामने रखी है।

(लेखक अधिवक्ता एवं स्वतंत्र परामर्शदाता हैं)

कानाफूसी

कांग्रेस की मुश्किल

दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की जबरदस्त जीत ने कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में नई समस्या खड़ी कर दी। पार्टी देश के सबसे बड़ी आबादी वाले प्रदेश में अपनी इकाई को नए सिरे से तैयार करना चाहती है लेकिन दिल्ली में आप की जबरदस्त जीत के बाद पार्टी के नेता, खासकर युवा नेता उसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। पार्टी महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा इससे खासी नाराज हैं। आप ने हाल ही में लखनऊ में एक रोड शो का आयोजन किया जिसमें प्रदेश कांग्रेस के कई नेता आप में शामिल हो गए। इनमें प्रदेश कांग्रेस की युवा इकाई के पूर्व अध्यक्ष नदीम अशरफ जायसी और पूर्व उपाध्यक्ष मनीष चौधरी भी शामिल हैं। जायसी खुद रायबरेली क्षेत्र से आते हैं और उन्हें एक समय गांधी परिवार का करीबी माना जाता था। गौरतलब है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस एक भी सीट हासिल नहीं कर पाई थी।

राहुल की कमी

आखिर राहुल गांधी कहां हैं ? यह सवाल उस समय एक बार फिर उठा जब दिल्ली में नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर छिड़ी हिंसा की घटनाओं के बाद वह कई अहम पार्टी बैठकों में नदारद नजर आए। वह बुधवार को पार्टी की उस बैठक में भी नहीं दिखे जो विशेष तौर पर दिल्ली के मौजूदा हालात पर चर्चा के लिए बुलाई गई थी। पार्टी ने लोक सभा और राज्य सभा के सभी सदस्यों को इसमें शामिल होने को कहा था। पार्टी सूत्रों ने राहुल का बचाव करते हुए कहा कि वह यात्रा पर हैं। परंतु पार्टी के एक दिग्गज नेता ने कहा कि राहुल गांधी की कमी महसूस की गई क्योंकि अभी भी भाजपा नेतृत्व के खिलाफ वही कांग्रेस का सबसे मजबूत दांव हैं।

आपका पक्ष

ऊर्जा से ही देश का विकास संभव

किसी भी देश के विकास में ऊर्जा की अहम भूमिका रही है। ऊर्जा से अर्थ प्राकृतिक संसाधनों से मिलने वाली ऊर्जा के स्रोतों जैसे ईंधन तथा मानव द्वारा निर्मित विद्युत ऊर्जा से है। वर्तमान में ईंधन और विद्युत ऊर्जा के बिना प्रगति असंभव है। आज जितने भी वाहन चल रहे हैं वे ईंधन या फिर विद्युत से चल रहे हैं। घरों में चलने वाले उपकरण बिजली बिना बेकार हो जाते हैं। अगर ईंधन न हो तो सार्वजनिक से लेकर निजी वाहन ठप पड़ जाएंगे। भारत ईंधन दूसरे देशों से आयात करता है तथा विद्युत ऊर्जा का स्वयं उत्पादन करता है। देश में पनबिजली, ताप बिजली तथा पवन ऊर्जा से विद्युत की आपूर्ति की जाती है। वर्तमान के आधुनिक युग में बिना ऊर्जा के एक घंटे बिताना भी मुश्किल है। सरकार सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के गांवों में बिजली पहुंचाने के लिए हर घर बिजली योजना की शुरुआत की थी जिसका मकसद हर घर में

बिजली पहुंच सके। सरकार के अनुसार आज भारत के हरेक गांवों में बिजली पहुंच चुकी है। लेकिन सिर्फ बिजली कनेक्शन पहुंचने भर से समस्या का अंत नहीं हो जाता है। आमतौर पर सभी जगहों में 24 घंटे बिजली नहीं मिल पाती है। अब सरकार का अगला कदम 24 घंटे बिजली आपूर्ति करने का लक्ष्य है। 24 घंटे निर्बाध बिजली प्रदान करना काफी मुश्किल है लेकिन अगर दृढ़ इच्छाशक्ति हो तो कोई भी काम असंभव नहीं है। तकनीक के साथ बिजली खपत भी कम हुई है। पहले 100 वॉट का बल्ब जलता था लेकिन अब 7 वॉट का बल्ब 100 वॉट के बल्ब के बराबर रोशनी प्रदान करता है। एलईडी बल्ब के आने से खपत कम हुई है। अगर किसी गांव में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति होती है तो वहां के लोगों की कई समस्याएं स्वत: खत्म हो जाएंगी तथा वहां विकास में अधिक समय नहीं लगेगा। बिजली आने से कई रोजगार का सृजन भी होगा तथा लोगों को कई तरह के नए काम मिलने लगेंगे। सरकार ने हाल में तापीय बिजली को मिलाकर नवीकरणीय ऊर्जा को मिलाकर 24 घंटे बिजली आपूर्ति की योजना बनाई है। इसके लिए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने वितरकों को 24 घंटे बिजली आपूर्ति को लेकर नीति का मसौदा भी जारी किया है। सरकार को इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए।

सरकार ने 24 घंटे बिजली प्रदान करने के लिए एक नीति मसौदा जारी किया है

रंजीत सिंह, नई दिल्ली

स्थानीय मुद्दे पर लोगों का जोर

हाल में हुए दिल्ली चुनाव के नतीजे से यह साफ है कि जनता लोकसभा और विधानसभा चुनावों में अलग-अलग प्राथमिकताएं तय करना सीख गई है। जनता अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की मुश्किलों का हल चाहती है, जैसे बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य आदि। केजरीवाल सरकार ने ये पांच चीजें जनता को कम से कम कीमत पर मुहैया कराई, जिस कारण राष्ट्रीय मुद्दे उनका कुछ नहीं बिगाड़ सके। उन्होंने चुनाव में अपने आप को स्थानीय मुद्दों तक सीमित रखा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में भारत जैसे गरीब और पिछड़े समाज में बिजली, पानी, स्कूल, परिवहन और अस्पतालों को जनसरोकारों से सीधे-सीधे जोड़ने की जो नई राजनीति शुरू की गई है, वह अन्य राज्यों के आने वाले चुनावों को अवश्य प्रभावित करेगी।

मो मंसूर आलम, प्रयागराज

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

संक्षेप में

गैर-बिजली क्षेत्रों में कोयला आपूर्ति बढ़ी

चालू वित्त वर्ष में जनवरी महीने तक कोल इंडिया की कोयला आपूर्ति बिजली क्षेत्र में 6.8 प्रतिशत कम हुई है, जबकि अन्य क्षेत्रों को की जाने वाले कोयला आपूर्ति 4.4 प्रतिशत बढ़ गई। कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि बिजली संयंत्रों की सुस्त मांग तथा बिजली संयंत्रों के पास कोयले का पर्याप्त भंडार होने के कारण इस क्षेत्र को कोयला आपूर्ति कम हुई है। कंपनी ने इसके कारण बिक्री में आ रही गिरावट दूर करने के लिए अन्य क्षेत्रों को कोयले की आपूर्ति बढ़ाने पर ध्यान दिया है। उन्होंने कहा, 'कोल इंडिया ने 2019-20 में जनवरी तक बिजली के अलावा अन्य क्षेत्रों को 954.5 लाख टन कोयले की आपूर्ति की है, जो साल भर पहले की तुलना में 4.4 प्रतिशत अधिक है।' वहीं इसी अवधि के दौरान बिजली क्षेत्र को कोल इंडिया की कोयला आपूर्ति 6.8 प्रतिशत गिरकर 37.78 करोड़ टन पर आ गई। कोल इंडिया के खदानों के निकास तथा बिजली संयंत्रों के पास अभी सम्मिलित तौर पर 782.5 लाख टन कोयले का भंडार है। आंकड़ों के अनुसार, 24 फरवरी तक बिजली संयंत्रों के पास 363.6 लाख टन कोयले का भंडार था, जो औसतन 20 दिन के लिए पर्याप्त है और करीब एक दशक का उच्च स्तर है। खदानों के निकास पर 416.3 लाख टन कोयले का भंडार है। *भाषा*

हल्दिया रिफाइनरी में बीएस-6 ईंधन का उत्पादन

सार्वजनिक क्षेत्र की इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) ने बीएस-6 मानकों को पूरा करने के लिए हल्दिया स्थित रिफाइनरी में करीब 3,000 करोड़ रुपये का निवेश किया है। एक अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। इसके अलावा आईओसी खड़गपुर में बॉटलिंग प्लांट और बजबज में डीजल एक्जॉस्ट फ्लूड (डीईएफ) संयंत्र तथा पहाड़पुर में ल्यूब ब्लेंडिंग यूनिट लगाने में 388 करोड़ रुपये और निवेश करेगी। कंपनी के कार्यकारी निदेशक प्रतीश भरत (पश्चिम बंगाल, सिक्कम और अंडमान निकोबार) ने कहा, 'आईओसी ने भारत चरण (बीएस)- 6 के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप पेट्रोल और डीजल उत्पादन को लेकर हल्दिया में रिफाइनरी को उन्नत बनाने के लिए 3,000 करोड़ रुपये का निवेश किया है।' उत्सर्जन का नया मानदंड 1 अप्रैल से अमल में आएगा। *भाषा*

निर्यात प्रतिबंध हटा, प्याज फिर चढ़ा

प्याज के दाम 30 प्रतिशत तक उछलकर दो सप्ताह के शीर्ष स्तर पर पहुंच गए

दिलीप कुमार झा
मुंबई, 27 फरवरी

सरकार द्वारा छह महीने पुराना निर्यात प्रतिबंध हटाए जाने का फैसला करने के बाद मांग में तीव्र इजाफे की वजह से आज प्याज के दाम 30 प्रतिशत तक उछलकर दो सप्ताह के शीर्ष स्तर पर पहुंच गए। बेंचमार्क लालसगांव मंडी की कृषि उपज विपणन समिति (एपीएमसी) में प्याज के आदर्श दाम गुरुवार को बढ़कर 21.50 रुपये प्रति किलोग्राम हो गए, जबकि एक दिन पहले दाम 16.50 रुपये प्रति किलोग्राम थे। प्याज के दामों का यह स्तर 11 फरवरी के बाद से नहीं देखा गया है।

केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने बुधवार देर शाम ट्वीट करके प्याज निर्यात प्रतिबंध हटाए जाने की घोषणा की थी जिसके बाद निर्यातकों ने तत्काल अपना कारोबार फिर से शुरू कर दिया। पासवान ने ट्वीट में कहा था, 'चूंकि प्याज के दाम स्थिर हो गए हैं और जोरदार रबी फसल की उम्मीद है, इसलिए सरकार ने इसके निर्यात से प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। इस साल मार्च में प्याज की मासिक उपज 40 लाख टन होने की उम्मीद है, जबकि पिछले साल इसी महीने उपज 28 लाख टन थी।'

व्यापारिक सूत्रों का मानना है कि निर्यात से प्रतिबंध हटाने के पक्ष में यह फैसला बुधवार को मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक के बाद लिया गया है। बैठक में 850 डॉलर प्रति टन न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) कम करने का भी फैसला लिया गया है। ये दोनों (निर्यात प्रतिबंध और एमईपी) फैसले छह महीने पहले लिए गए थे। तब थोक बाजार में प्याज के दाम बढ़कर 80 रुपये प्रति किलोग्राम हो गए थे जो खुदरा में 140 से 160 रुपये प्रति किलोग्राम थे। महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश समेत प्रमुख उत्पादक राज्यों में प्रलयकारी बाढ़ की वजह से खरीफ की फसल को हुए भारी नुकसान के कारण करीब छह महीने पहले प्याज के दामों में तेज इजाफा हुआ था।

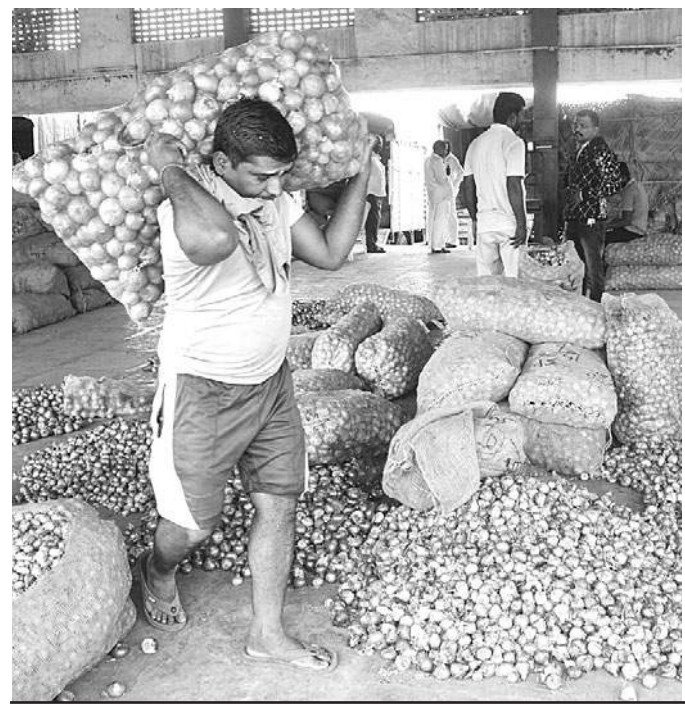

लालसगांव में दाम

दिन	रुपये/क्विंटल
10 फरवरी	2,101
11 फरवरी	2,150
12 फरवरी	1,900
13 फरवरी	1,860
14 फरवरी	1,850
15 फरवरी	1,940
17 फरवरी	2,000
18 फरवरी	2,050
19 फरवरी	2,060
20 फरवरी	2,025
22 फरवरी	2,000
24 फरवरी	1,800
25 फरवरी	1,650
27 फरवरी	2,150

स्रोत- एनएचआरडीएफ
संकलन- बीएस रिसर्च

अलबत्ता प्रतिबंध हटाने का यह फैसला विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी करने के बाद ही प्रभावी होगा। एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी लासलगांव की कृषि उपज विपणन समिति के सचिव एनएस वाधवाने ने कहा, 'निर्यातकों ने भविष्य की खेप के लिए बड़ी मात्रा में प्याज की बुकिंग करनी शुरू कर दी है। निर्यात से प्रतिबंध हटने के बाद निर्यातकों की मांग बढ़ने की वजह से ही भारी आवक के बावजूद आज प्याज के दामों में तेजी आई है।' गुरुवार को लासलगांव में 1,500 टन प्याज आवक दर्ज की गई, जबकि बुधवार को आवक 1,000 टन थी।

> केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने बुधवार देर शाम ट्वीट करके प्याज निर्यात प्रतिबंध हटाए जाने की घोषणा की थी जिसके बाद निर्यातकों ने तत्काल अपना कारोबार फिर से शुरू कर दिया

हालांकि वाधवाने का मानना है कि दामों का यह स्तर अस्थायी है। फिलहाल मंडियों में खरीफ के आखिरी सत्र से प्याज की आवक हो रही है। शीघ्र खराब होने की वजह से इसका ज्यादा लंबे समय तक भंडारण नहीं किया जा सकता है। इसलिए खरीदारों को इसकी खरीद के कुछ ही दिनों में बिक्री करनी होती है। सामान्य रूप में कारोबारी और स्टॉकिस्ट रबी सत्र की फसल का अपना स्टॉक तैयार करते हैं जो मंडियों में आनी शुरू हो गई है, लेकिन इसकी आवक काफी कम मात्रा में हो रही है। अब से दो सप्ताह बाद रबी सत्र की आवक पूरे जोरों पर होने वाली है जिससे प्याज के दामों में और गिरावट आ सकती है। इस बीच राज्य सरकार द्वारा लगाई गई स्टॉक सीमा ने कारोबारियों और स्टॉकिस्टों को परेशान कर रखा है। दिसंबर 2019 में महाराष्ट्र सरकार ने खुदरा विक्रेताओं के लिए स्टॉक सीमा आधी करके पांच टन और स्टॉकिस्टों के लिए 25 टन कर दी थी।

पुणे की अंबेगांव एपीएमसी के चेयरमैन देवदत्त जयवंतराव ने कहा, 'राज्य सरकार ने प्याज की स्टॉक सीमा में ढील देने के लिए पहले ही प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्टॉक सीमा हटाने से खास तौर पर निर्यातकों और स्टॉकिस्टों को राहत की सांस मिलेगी।'

नाशिक स्थित प्याज किसान और व्यापारी संजय सनप ने कहा कि खरीफ के शुरुआत में की गई बुआई की फसल बाढ़ में बहने के बावजूद किसानों ने कुछ हिस्सों में दो और तीन बार प्याज की बुआई की थी जिसके परिणामस्वरूप खेती की लागत में इजाफा हुआ है। इस कारण प्याज के मौजूदा दाम किसानों के लिए लाभकारी हैं।

इंडिया रेटिंग्स ऐंड रिसर्च ने की

इस्पात क्षेत्र की रेटिंग ऋणात्मक

अदिति दिवेकर
मुंबई, 27 फरवरी

इंडिया रेटिंग्स ऐंड रिसर्च (इंड-रा) ने वित्त वर्ष 21 के लिए घरेलू इस्पात क्षेत्र पर अपना दृष्टिकोण संशोधित करके ऋणात्मक कर दिया है। पहले यह 'स्थिर-से-ऋणात्मक' के बीच था। लौह अयस्क के दामों में जोखिम के कारण मार्जिन के दबाव और इस्पात मांग में पांच प्रतिशत की सीमित वृद्धि (जो वित्त वर्ष 20 में अनुमानित रूप से चार प्रतिशत थी) की संभावना को देखते हुए ऐसा किया गया है। एजेंसी ने कहा है कि नए खदान मालिकों (निजी उपभोग और व्यापारिक) के लिए लौह अयस्क पर अधिक भुगतान करने से इस्पात मिलों की लागत की स्थिति बदल सकती है।

इंड-रा ने वित्त वर्ष 20 और वित्त वर्ष 21 के लिए सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान क्रमश: पांच और 5.5 प्रतिशत जताया है। इसमें सुस्त आर्थिक गतिविधियों की झलक दिखती है। इससे इस्पात क्षेत्र में मांग वृद्धि पर असर जारी रहेगा और किसी खास तेजी की संभावना भी नहीं है।

इंड-रा का मानना है कि वित्त वर्ष 21 में 5.3 प्रतिशत के सकल पूंजी निर्माण की ही तरह इस्पात मांग वृद्धि सीमित रहेगी।

हालिया खदान नीलामी में बोलीदाताओं और अंतिम भुगतान के बीच जोरदार प्रतिस्पर्धा के संकेतों को ध्यान में रखते हुए इंड-रा को इस बात के आसार दिखते हैं कि गैर-एकीकृत और नए निजी उपभोग वाले इस्पात उत्पादकों पर लागत का दबाव बनेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि हाल ही में नीलाम की गई लौह अयस्क खदानों में से लगभग एक-चौथाई के लिए औसत भुगतान 100 प्रतिशत से ज्यादा रह सकता है। इसके परिणामस्वरूप लौह अयस्क की कीमतों में खासा इजाफा होगा। भले ही इसमें से कुछ भाग व्यापारी खनिकों द्वारा वहन किया जाए।

- नए खदान मालिकों के लिए लौह अयस्क पर अधिक भुगतान करने से इस्पात मिलों की लागत की स्थिति बदल सकती है
- इंड-रा का मानना है कि वित्त वर्ष 21 में 5.3 प्रतिशत के सकल पूंजी निर्माण की ही तरह इस्पात मांग वृद्धि सीमित रहेगी

कोरोनावायरस के प्रकोप से बढ़ती जटिलता के बीच चीन की इस्पात मांग वृद्धि का जोखिम भी वैश्विक और घरेलू इस्पात के दामों को प्रभावित कर सकता है। हालांकि आयातित कोकिंग कोल और अंतरराष्ट्रीय लौह अयस्क के दामों में नरमी से कुछ लाभ होने की उम्मीद है।

अगर चीनी इस्पात उत्पादक वित्त वर्ष 21 में आवासीय विनिर्माण और आर्थिक वृद्धि में नरमी के कारण मांग में होने वाली कमी के अनुरूप अपने उत्पादन में कटौती नहीं करते हैं, तो यह वैश्विक इस्पात के दामों के लिए जोखिम हो सकता है। एजेंसी को उम्मीद है कि हल्के-से इजाफे के साथ वित्त वर्ष 21 में कुल इस्पात मार्जिन नरम रहेगा।

कई और देश कोरोना की चपेट में

कई देशों की सरकारों ने दुनिया भर पर फैल रहे कोरोनावायरस को काबू करने के लिए उपाय करने शुरू कर दिए हैं क्योंकि चीन के बाहर पहली बार संक्रमण के ज्यादा नए मामलों की पुष्टि हुई है। ऑस्ट्रेलिया और ताइवान ने भी आपातकालीन स्थिति के लिए उपाय करना शुरू कर दिया है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने दुनिया भर में स्वास्थ्य संकट को देखते हुए उपराष्ट्रपति माइक पेंस को जिम्मेदारी दी है जो वैश्विक संकट पर अमेरिका की तरफ से प्रतिक्रिया देने वाले प्रभारी होने के साथ-साथ अमेरिका में भी कोरोनावायरस के खिलाफ प्रशासन के प्रयासों का नेतृत्व करेंगे।

भारत से लौटने के कुछ घंटे बाद ट्रंप ने अमेरिका में स्थिति का जायजा लेने के लिए बुधवार को कई दौर की बैठक की। कैलिफॉर्निया में एक व्यक्ति के संक्रमित होने की पुष्टि की गई जिसकी यात्रा का कोई रिकॉर्ड नहीं है। अधिकारियों ने बताया कि न्यूयॉर्क सिटी में भी दर्जनों लोगों की जांच की गई हालांकि यहां संक्रमण के किसी मामले की पुष्टि नहीं की जा सकी।

अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने वायरस संक्रमण के संकट को देखते हुए अपना संयुक्त सैन्य अभ्यास टालने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि देश में वायरस संक्रमण के 23 मामलों की पुष्टि हुई है और वहां के अस्पतालों में स्वास्थ्य आपूर्ति, निजी सुरक्षा उपकरण और पर्याप्त स्वास्थ्य कर्मियों की मौजूदगी सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है। मॉरिसन ने कैनबरा में कहा, 'दुनिया जल्द ही घातक कोरोनावायरस महामारी की चपेट में आ सकती है। इसी वजह से हम सबकी सहमति के साथ कोरोनावायरस के लिए आपात योजना बनाने की पहल की की जा रही है।'

दक्षिण कोरिया के सोल में गुरुवार को विषाणुनाशक का छिड़काव करते स्वास्थ्यकर्मी

- चीन में मरने वालों की संख्या **2,800** हुई
- दक्षिण कोरिया में वायरस के कुल **1,766** मामले सामने आए
- चीन के वुहान से **76** भारतीयों, **36** विदेशियों को भारत लाया गया
- वायरस के कारण सऊदी अरब ने मक्का और काबा की यात्रा पर लगाई रोक
- ईरान में कोरोनावायरस के **245** पुष्ट मामलों में **26** की हुई मौत
- जापान के प्रधानमंत्री ने देशभर के स्कूल बंद करने की अपील की
- अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने सैन्य अभ्यास टालने का फैसला किया
- दुनिया भर के बाजारों में छठे दिन भी गिरावट जारी

बाजार में निराशा

वैश्विक बाजारों में लगातार छठे दिन गिरावट देखी गई और 3.6 लाख करोड़ डॉलर से अधिक पूंजी गंवा दी गई। तेल की कीमतों में भी गिरावट देखी गई। कोरोनावायरस की वजह से अब तक 80,000 से अधिक संक्रमित हो चुके हैं और करीब 2,800 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से ज्यादातर मौत चीन में हुई है। इस महामारी के प्रकोप से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन में करीब एक महीने से अधिक वक्त से आर्थिक गतिविधियां बंद हैं ऐसे में नुकसान की पूरी गुंजाइश है लेकिन इसका अंदाजा अभी नहीं मिल सका है।

चीन के बाहर इटली, ईरान और दक्षिण कोरिया में वायरस का संक्रमण ज्यादा दिखा है। जापान में संक्रमण के 190 से अधिक मामले की पुष्टि हो चुकी है ऐसे में ओलिंपिक खेलों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं जो टोक्यो में 24 जुलाई से शुरू होने हैं। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने गुरुवार को वायरस फैलने से रोकने के लिए 2 मार्च से सभी स्कूलों को बंद करने की अपील की। आबे ने कहा, 'सरकार के लिए बच्चों का स्वास्थ्य और सुरक्षा सर्वोपरि है।'

चीन के बाहर 3,246 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हो चुकी है जिनमें से 51 लोगों की मौत हुई है। पिछले कुछ दिनों में कई अन्य देशों ने भी संक्रमण के पहले मामले की पुष्टि की है इनमें पाकिस्तान, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, ग्रीस और रोमानिया जैसे देश शामिल हैं। इराक में संक्रमण के छठे मामले की पुष्टि गुरुवार को हुई है जबकि कुवैत में संक्रमित लोगों की तादाद बढ़कर 43 हो गई।

ब्राजील ने भी लैटिन अमेरिका में पहले संक्रमण के मामले की पुष्टि की है। उधर दक्षिण कोरिया में संक्रमण के 334 नए मामले सामने आए हैं जिससे संक्रमित होने वाले लोगों की कुल तादाद 1,766 हो गई है। चीन के बाद दक्षिण कोरिया ही दूसरा ऐसा देश हैं जहां संक्रमण के ज्यादा मामले की पुष्टि की गई है। इटली में संक्रमण के 400 से अधिक मामले की पुष्टि की गई है। ईरान में कुल 245 मामले सामने आए हैं। चीन ने कहा कि गुरुवार को संक्रमण से मरने वालों की तादाद 29 रही जो अब तक एक दिन में मरने वालों की सबसे कम संख्या है हालांकि संक्रमण के 433 नए मामले सामने आए हैं। सालाना हज यात्रा से पहले वायरस संक्रमण की आशंका को देखते हुए सऊदी अरब ने गुरुवार को इस्लाम के सबसे पवित्र स्थलों की यात्रा पर रोक लगा दी है। *एजेंसियां*